घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 69- गुरूवार 08- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

ट्रम्प का मोदी पर बयान, राहुल बोले...

फर्क समझो सरजी,इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था,ट्रम्प के आगे मोदी सरेंडर

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। राहुल ने X पर 'फर्क समझो सर जी' कैप्शन के साथ 3 जून का वीडियो शेयर किया। राहुल ने कहा- मोदी ट्रम्प के आगे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। आपको वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं था, सातवां फ्लीट आया था। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और हथियार भेजे थे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, 'मुझे जो करना है, मैं करूंगी। राहुल ने कहा, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरा सा दबाव डालो वे सरेंडर कर देते हैं। मैं अब इन बीजेपी-आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाएंगे। राहुल का यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें ट्रम्प ने कहा था- प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और कहा सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं।

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला...मेरिट में जनरल कट-ऑफ पार करने पर मिलेगी सामान्य सीट

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की जटिल व्यवस्था को लेकर दो अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिनका देश की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों की चयन प्रक्रिया पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को आए इन फैसलों के माध्यम से अदालत ने यह सिद्धांत स्पष्ट कर दिया है कि योग्यता (मेरिट) हमेशा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी प्रतिभा के दम पर सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी की सीट के बजाय सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की सीट आवंटित की जानी चाहिए। यह व्यवस्था आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के उम्मीदवारों के लिए भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के समीकरण बदल देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्टता प्रदान की कि आरक्षण का लाभ कब नहीं दिया जा सकता। इस मामले में अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार ने भारतीय वन सेवा की परीक्षा दी थी।

पटना हाई कोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश,न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

पटना, 07 जनवरी 2026। पटना उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। शपथग्रहण के बाद न्यायमूर्ति साहू ने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंथ्री के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी ग्रहण की। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुधीर सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व निभा रहे थे। शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा,विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार,जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सहित पटना उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश,वरिष्ठ अधिवक्ता,प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे : सुप्रीम कोर्ट

स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत,वे बच्चों-बड़ों को काट रहे,लोग मर रहे

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। बहस में कुत्तों के मूड, कुत्तों की काउंसलिंग,कम्युनिटी डॉग्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डॉग्स जैसे शब्द सामने आए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं,बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। पीठ ने सवाल उठाया कि स्कूलों,अस्पतालों और अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। बुधवार को मामले की सुनवाई ढाई घंटे तक चली। अगली सुनवाई 8 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से फिर शुरू होगी। बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि जो कुत्ता काटे उसकी नसबंदी की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा, अब तो बस एक ही चीज बाकी है,कुत्तों को भी काउंसलिंग देना। ताकि वापस छोड़े जाने पर वह

काटे नहीं। इस बीच सिब्बल ने कहा, जब भी मैं मंदिरों वगैरह में गया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया- 'आप खुशकिस्मत हैं। लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है। लोग मर रहे हैं।' कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2018 में एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। ये ठीक से लागू क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों के कमजोर अमल से जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए।

कल सोसाइटी में कोई भैंस ले आएगा तो क्या करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा...'यही बात गेटेड कम्युनिटी पर भी लागू होती है। गेटेड कम्युनिटी में कुत्ते को घूमने देना चाहिए या नहीं, यह समुदाय को तय करना होगा। मान लीजिए,90 प्रतिशत निवासियों को लगता है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन 10 फीसदी कुत्ते रखने पर जोर देते हैं। कोई कल भैंस ला सकता है। वे कह सकते हैं कि मुझे भैंस का दूध चाहिए।'

कुत्तों को लेकर गेटेड कम्युनिटी कर सकें फैसला, होना चाहिए प्रावधान : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत गेटेड कम्युनिटी मतदान के जरिए फैसला ले सके। वकील वंदना जैन ने कहा...'हम कुत्तों के खिलाफ नहीं हैं। हमें कुत्तों के खतरे और सार्वजनिक सुरक्षा को देखना होगा। 6.2 करोड़ कुत्तों की आबादी है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।' मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सवाल करते हुए कहा...'क्या कुत्तों को यह सिखाया जा सकता है कि वे किसी को न काटें? किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता काटने के मूड में है या नहीं?' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशुप्रेमियों को शेल्टर में मौजूद कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए।

आईसीजीएस समुद्र प्रताप भारत की समुद्री सुरक्षा में मील का पत्थर: पीएम मोदी

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारतीय तटरक्षक पोत 'आईसीजीएस समुद्र प्रताप' के नौसेना बेड़े में शामिल होने की सराहना की और इसे देश की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक जहाज के शामिल होने से भारत की तटीय निगरानी और समुद्री हितों की सुरक्षा को और ताकत मिलेगी। यह पोत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करेगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था को नई धार देता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'आईसीजीएस समुद्र प्रताप कई वजहों से खास है। यह जहाज न सिर्फ सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई नई तकनीक पर्यावरण को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल संचालन को बढ़ावा देती है।' प्रधानमंत्री ने कहा, इस जहाज का कमीशन होना भारत की समुद्री यात्रा में एक अहम पड़ाव है। यह दिखाता है कि देश अब रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मामले में सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यह आत्मनिर्भरता की हमारी सोच को मजबूत करता है।

झारखंड में हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मारा

7 दिन में 16 लोगों की जान ली,वन विभाग ने अंबानी के वनतारा से मदद मांगी

झारखंड,07 जनवरी 2026। झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथी ने मंगलवार रात 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। यह सभी अपने घर में सो रहे थे। यह हाथी पिछले 7 दिन में इलाके के 16 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में वन विभाग के अफसरों ने अनंत अंबानी के वन्यजीव संरक्षण संगठन 'वनतारा' से मदद मांगी है।

मरने वाले सभी 6 लोग एक ही घर के

चाईबासा जिले के नोवामुंडी प्रखंड के जेटिया पंचायत के भरबरिया गांव में हाथी ने जिन 6 लोगों को कुचलकर मार डाला,वह एक ही घर में सो रहे थे। रात करीब 10 बजे जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक हाथी ने घर पर हमला कर दिया। हमले में सनातन मेराल,उनकी पत्नी जोंकों कुई, उनके दो बच्चे और परिवार के दो और सदस्य मारे गए। एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। हमले में घर के दो अन्य लोग गंभीर घायल हैं।

हाथी बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहा : डीएफओ

चाईबासा के डीएफओ आदित्य नारायण ने कहा हाथी बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे उसे लगातार ट्रेस कर पाना वन विभाग की टीमों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है, जो हाथी को ट्रेंकुलाइज कर काबू करने में मदद करेगी। इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण संगठन 'वनतारा' की टीम को भी बुलाया गया है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की पूरी टीम प्रभावित इलाकों में लगातार घूम रही है,ड्रोन और अन्य संसाधनों की मदद से हाथी की मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है,ताकि किसी भी नए गांव में नुकसान होने से पहले अलर्ट किया जा सके।

दिनभर जंगल में छिपकर रहता है हाथी

सरकार और प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हाथी दिनभर जंगल में छिपकर रहता है। अंधेरा होते ही वह गांवों की ओर मूव करता है। इस दौरान रास्ते में दिखने वाले घरों पर अटैक करता है। सोते हुए लोगों को भी हाथी पटक कर और घसीटकर मार रहा है।

अब थर्मल सेंसर ड्रोन से चौकसी होगी

वन विभाग की तकनीकी टीम अब हाथी का पता लगाने के लिए रात को थर्मल सेंसर ड्रोन उड़ाएगी। बुधवार शाम को तकनीकी टीम पहुंच गई है।

निकाय चुनाव....अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस गठबंधन कुछ घंटों में टूटा

कांग्रेस ने भी 12 पार्षद निलंबित किए,अकोट में ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया था

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। महाराष्ट्र की अंबरनाथ और अकोट नगर पालिका चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को अप्रत्याशित गठबंधन देखने को मिले। अंबरनाथ नगर पालिका में भाजपा ने कांग्रेस-एनसीपी से हाथ मिलाया। वहीं, अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया। हालांकि ये गठबंधन कुछ ही घंटों में टूट गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को इन गठबंधन को

खारिज कर दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने भी अंबरनाथ के 12 पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अंबरनाथ नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं। बहुमत के लिए 31 उम्मीदवार चाहिए थे। चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इसके बावजूद वह सत्ता से बाहर रह गई। दरअसल, भाजपा ने चुनाव के बाद कांग्रेस और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' नाम से गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन के जरिए नगर परिषद में बहुमत जुटाया गया और परिषद का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया गया। इसके चलते भाजपा की सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) को सत्ता से बाहर कर दिया गया। इस गठबंधन के समर्थन से भाजपा नेता तेजश्री करंजुले को अंबरनाथ नगर परिषद की अध्यक्ष (मेयर) चुना गया। यह गठजोड़ इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विरोध करती रही है, लेकिन अंबरनाथ में सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया।

सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले- कार्रवाई की जाएगी

महाराष्ट्र में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति सरकार चला रही है। बावजूद इसके स्थानीय चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन किया,जिसे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया है।

मप्र के इंदौर में दूषित पानी से अब तक 20 की मौत

प्रशासन ने 6 की पुष्टि की लेकिन मुआवजा 18 को दिया

इंदौर,07 जनवरी 2026। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। दरअसल,मंगलवार तक क्षेत्र में मृतकों की संख्या 18 थी,लेकिन प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनाई गई सूची में बुधवार को दो नए नाम जोड़े हैं। इनमें रामकली जगदीश और श्रवण नत्थु खुपराव शामिल हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायालय में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, उसमें केवल चार मौतों का जिक्र था, लेकिन मुआवजा 18 मृतकों के परिवारों को दिया गया है। इन्हें 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि दूषित पानी से भले ही 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जहां भी मौत की सूचना मिल रही है,वहां क्रॉस चेक कर आर्थिक सहायता दी जा रही है।

बुधवार को आईसीयू में 16 मरीजों के भर्ती होने की जानकारी सामने आई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी ने बताया कि वर्तमान में कुल 99 मरीज अस्पताल में भर्ती है,जिनका उपचार किया जा रहा है। मृतकों में उर्मिला यादव (60),नंदलाल पाल (75),उमा कोरी (31),मंजुला (74), ताराबाई कोरी (60),गोमती रावत (50),सीमा प्रजापत (50),जीवन लाल (80),अव्यान साहू (पांच माह),हरकुंवर बाई (70),अरविंद लिखर,गीताबाई,अशोक लाल पंवार,संतोष बिगोलिया,ओमप्रकाश शर्मा, रामकली,श्रवण खुपराव,हीरालाल (60),शंकर भाया (70) और सुमित्रा बाई शामिल हैं। प्रशासन ने मृतकों की सूची में जिन दो नामों को जोड़ा है,उनमें रामकली (47) पत्नी जगदीश को गत 28 दिसंबर को अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। परिजन उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे,लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि रामकली को इससे पहले किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं थी। वहीं, श्रावण नथ्थु खुपराव की 29 दिसंबर को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। उनके बेटे श्रीकृष्ण ने बताया कि 25 दिसंबर को उन्हें अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन 26 दिसंबर को कुछ सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद अचानक तबीयत फिर बिगड़ी और उनकी जान चली गई। श्रावण खुपराव का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के सेलापुर गांव में किया गया,जो उनका पैतृक गांव है। उनका पोता नगर निगम की पानी की टंकी पर कार्यरत है और बेटा सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता है,इसी कारण पूरा परिवार इंदौर में रह रहा था। इंदौर में मौत के आंकड़ों और जिन्हें मुआवजे दिया गया है,उनकी संख्या में अंतर को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना कष्टदायक है इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बुधवार को भी भागीरथपुरा क्षेत्र की बस्तियों और कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीवरेज और नर्मदा पाइपलाइन के लीकेज सुधार के कामों का जायजा लिया और दिशा-निर्देश दिए।

ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी फर्म का दावा...

पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई,भारत ने भी संपर्क किया था

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं। इसके मुताबिक पिछले साल अप्रैल में भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने डिप्लोमैट के जरिए लॉबिंग की थी। इसके तहत अमेरिका में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों,सांसदों,पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों के साथ करीब 60 बार संपर्क किया था। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमेरिकी न्याय विभाग में दाखिल दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल,वन-टु-वन बैठकों के जरिए अप्रैल अंत से लेकर 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक संघर्ष विराम के लिए बैठकें जारी रखी थीं। पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत पर अमेरिका का दबाव बनाकर युद्ध रुकवाना चाहता था। उसने ट्रम्प प्रशासन तक तेजी से पहुंच बनाने, व्यापार और कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित

करने के लिए 6 लॉबिंग फर्मों पर करीब ?45 करोड़ खर्च किए थे। अमेरिकी लॉबिंग फर्म एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार और उसके अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने के लिए फर्म की सेवाएं ली थीं। अमेरिकी लॉबिंग फर्म एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन के साथ कई अहम मुद्दों पर भारतीय दूतावास की बातचीत में मदद की गई।

संपादकीय

संगठन की अनदेखी करती कांग्रेस

स्थानीय जनता और नेतृत्व की आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं

जमीनी समझ वाले स्थानीय नेतृत्व को उभारने और संगठन बनाने पर जोर देने की वे कवायद कर रहे हैं। उनका मानना है कि सिर्फ नैरेटिव गढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए जमीनी संघर्ष का माद्दा भी होना चाहिए। शशि थरूर पहले से ही ऐसे संकेत दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान उनकी अनदेखी कर रहा है। कुछ ऐसा ही दिग्विजय के साथ भी हो सकता है...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गत दिनों अपनी एक्स पोस्ट में लिखा,'आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ-भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है।'इन शब्दों के मायने तब खुलते हैं, जब इसके साथ चस्पां एक तस्वीर दिखती है। 1995 की उस तस्वीर में नरेन्द्र मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास फर्श पर बैठे हैं। दिग्विजय सिंह के ये शब्द कांग्रेस नेतृत्व और संगठन के कामकाज पर एक तरह से टिप्पणी हैं।

कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली और संगठन की लचर हालत पर टिप्पणी करने वाले दिग्विजय पहले शख्स नहीं हैं। केंद्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी के उभार के बाद कांग्रेस लगातार फिसल रही है। हाल में उसे और उसके सहयोगी दलों को उस बिहार में भी हार झेलनी पड़ी,जिसे महज दो महीने पहले ही वह जीता हुआ मान चुकी थी। उसकी निराशा महाराष्ट्र और गोवा के निकाय चुनावों ने भी बढ़ाई है। इस बीच केरल के निकाय चुनावों ने उसे जरूर सांत्वना दी है, लेकिन वह इतनी कारगर नहीं है कि पार्टी और उसके जमीनी कार्यकर्ता भविष्य के प्रति व्यापक रूप से आश्वस्त हो सकें।

कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खरगे हों,लेकिन सबको पता है कि पार्टी की असल कमान किसके हाथ है। पार्टी के असल बास राहुल गांधी हैं। इस लिहाज से पार्टी उन्हीं के हिसाब से चल रही है। राहुल तेजतर्रार और आक्रामक हैं, लेकिन उनकी यह आक्रामकता नतीजों में नहीं बदल रही। उनकी शैली एक हद तक वामपंथी वैचारिकी और राजनीति की तरह है। वामपंथी नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहते हैं,लेकिन नतीजों के मोर्चे पर नाकाम रहते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने'चौकीदार चोर'का नैरेटिव तैयार किया। 2024 में 'खतरे में संविधान' का आख्यान खड़ा किया। हाल में 'वोट चोरी' का आरोप चस्पां किया। वामपंथी इकोसिस्टम के जरिये ये सारे इस कदर स्थापित हुए कि लगा कि इनकी चक्करघिन्नी में भाजपा फंस गई। भाजपा कई बार चिंतित भी दिखी, लेकिन उसके नेतृत्व ने होश नहीं खोया।

नतीजे सामने हैं। कांग्रेस के कई नैरेटिव उलटे भी पड़ते हैं,क्योंकि वे जमीनी समझ के बिना गढ़े जाते हैं। बिहार के संदर्भ में पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग का मानना है कि जब राहुल ने वोटर जागरूकता यात्रा निकाली,तब मिथिला समेत उत्तर बिहार में सवर्ण,विशेषकर सवर्ण मतदाताओं का कांग्रेस को लेकर रुख बदल रहा था,लेकिन बाद में उन्हीं ब्राह्मणों और सवर्णों को आततायी बताने का नैरेटिव गढ़ा गया,लिहाजा मतदान में हालात बदल गए। अपने वामपंथी सोच के चलते कांग्रेस से समूचे देश का सवर्ण मतदाता दूर होता जा रहा है। और तो और जब देश और संसद में ज्यादा जरूरत होती है,तब राहुल विदेश में भाषण दे रहे होते हैं। इसके चलते संगठन की लगातार अनदेखी हो रही है।

कांग्रेस के कई अहम सूत्र एकमत हैं कि संगठन को दुरुस्त करने पर पार्टी नेतृत्व का ध्यान नहीं है। उदाहरण के लिए,लोकसभा चुनाव के वक्त हरियाणा में न तो सचिव था,न ही पार्टी की जिला कमेटियां काम कर रही थीं। ऐसा ही हाल बिहार का भी था। जिला स्तरीय कमेटियां थी नहीं। कई राज्य ऐसे हैं, जहां अध्यक्ष तो बना दिए गए हैं,लेकिन वहां कमेटी ही नहीं है। मुंबई में तो बीएमसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन तक पता ही नहीं रहा कि कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ है और कौन कहां से लड़ेगा। मनरेगा का नाम और चेहरा बदलने के खिलाफ कांग्रेस राज्यों की राजधानियों में रैलियां करने जा रही है। इस पर पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि दूसरी रैलियों की ही तरह इन रैलियों का भी हश्र होगा। उनके हिसाब से ब्लाक स्तर पर मनरेगा के जाब कार्डधारकों का विरोध-प्रदर्शन आयोजित होना चाहिए था फिर जिला स्तर पर उन्हें जुटाया जाता। बाद में राज्यों की राजधानी और दिल्ली में उनका जुटान होता। इससे पार्टी की बात निचले स्तर तक पहुंचती और नए वोटर भी बनते।

भाजपा आज अगर चुनाव जीत रही है तो इसकी वजह यह नहीं है कि वह सिर्फ अपने राष्ट्रीय नैरेटिव के सहारे चुनाव लड़ती है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के अपने केंद्रीय विचार के साथ ही वह स्थानीय हालात के लिहाज से रणनीति बनाती है और उस पर अमल करती है। वह स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखती है, लेकिन कांग्रेस यहां चूक रही है। वह समूचे देश में अपने केंद्रीय नैरेटिव के सहारे चुनाव लड़ती है,स्थानीय जनता और नेतृत्व की आकांक्षाओं और संस्कृति का वह ख्याल नहीं कर रही।

उसकी नाकामियों पर ब्रेक नहीं लगने की एक बड़ी वजह उसका यह सोच भी है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की इन्हीं खामियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रणनीति बदलने का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी समझ वाले स्थानीय नेतृत्व को उभारने और संगठन बनाने पर जोर देने की वे कवायद कर रहे हैं। उनका मानना है कि सिर्फ नैरेटिव गढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए जमीनी संघर्ष का माद्दा भी होना चाहिए। शशि थरूर पहले से ही ऐसे संकेत दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान उनकी अनदेखी कर रहा है। कुछ ऐसा ही दिग्विजय के साथ भी हो सकता है।

वेनेजुएला संकट के बहाने वैश्विक शक्ति-संतुलन

हाल ही में वेनेजुएला में घटित राजनीतिक घटनाक्रम और उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। अनेक विश्लेषक इसे उन्नीसवीं सदी के मुनरो सिद्धांत की संभावित वापसी के रूप में देख रहे हैं। मुनरो सिद्धांत मूलतः यह घोषित करता था कि पश्चिमी गोलार्द्ध में किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा और इस क्षेत्र को अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखेगा। समय के साथ यह सिद्धांत उपनिवेशवाद-विरोधी आदर्श से हटकर अमेरिकी प्रभुत्व और हस्तक्षेपवादी नीति का औजार बन गया। आज, जब विश्व बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, तब वेनेजुएला जैसे देशों में अमेरिकी दखल यह संकेत देता है कि शक्ति-राजनीति के पुराने सिद्धांत नए संदर्भों में फिर उभर रहे हैं...

डॉ. सत्यवान सौरभ
बड़वा भिवानी,हरियाणा

वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक संकट,राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दबावों से जूझ रहा है। अमेरिका ने लोकतंत्र,मानवाधिकार और आर्थिक कुप्रबंधन के नाम पर वहां प्रतिबंधों और राजनीतिक हस्तक्षेप को उचित ठहराया है। किंतु आलोचकों का मानना है कि इसके पीछे असली कारण वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधन और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति है। यह वही सोच है जो ऐतिहासिक रूप से मुनरो सिद्धांत के अंतर्गत विकसित हुई थी, जहाँ अमेरिका स्वयं को पूरे क्षेत्र का संरक्षक मानता रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम में ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रियाएँ विशेष ध्यान आकर्षित करती हैं। चीन और रूस ने अमेरिकी हस्तक्षेप का खुलकर विरोध किया और इसे संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके वक्तव्यों में न केवल वेनेजुएला के समर्थन का स्वर था, बल्कि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देने की व्यापक रणनीति भी निहित थी। इसके विपरीत,भारत का वक्तव्य अपेक्षाकृत संतुलित,संयमित और कूटनीतिक रहा। भारत ने न तो अमेरिका की नीति का समर्थन किया और न ही तीखा विरोध। यह अंतर भारत की विदेश नीति की विशिष्टता और उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। भारत के इस संतुलित रुख के पीछे सबसे प्रमुख कारण उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने किसी एक शक्ति गुट में शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा अपनाई है। शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका उदाहरण था, और आज के बहुध्रुवीय विश्व में यह नीति और भी प्रासंगिक हो गई है। अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है,विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में। ऐसे में वेनेजुएला जैसे मुद्दे पर तीखा विरोध भारत-अमेरिका संबंधों को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकता था।

साथ ही,भारत रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है। इस दोहरे संतुलन के लिए भारत को शब्दों और रुख में अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। भारत की कूटनीति टकराव से अधिक संवाद पर विश्वास करती है और यही कारण है कि वह विवादास्पद

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अक्सर संतुलित भाषा का प्रयोग करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भारत की स्वयं की संवेदनशीलताएँ हैं। भारत लंबे समय से संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करता रहा है, क्योंकि वह स्वयं कश्मीर और अन्य आंतरिक मुद्दों पर बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। यदि भारत वेनेजुएला के मामले में किसी एक पक्ष के समर्थन में अत्यधिक मुखर होता,तो भविष्य में उसके अपने मामलों पर भी प्रश्न उठाए जा सकते थे। इसलिए भारत ने सिद्धांतों का समर्थन करते हुए भी व्यावहारिक संतुलन बनाए रखा।

भारत का संतुलित वक्तव्य यह भी दर्शाता है कि वह स्वयं को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। भारत का उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देना है। यही कारण है कि भारत अक्सर शांतिपूर्ण समाधान,बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देता है। यह रुख उसे वैश्विक दक्षिण के देशों में एक भरोसेमंद और संतुलित नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत के लिए लैटिन अमेरिका का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब तक यह क्षेत्र भारत की विदेश नीति में अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा है,किंतु वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ इस सोच में बदलाव की माँग करती हैं। लैटिन अमेरिका ऊर्जा संसाधनों,विशेषकर तेल और गैस, के साथ-साथ लिथियम, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का भी बड़ा स्रोत है। हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में ये संसाधन भारत की आर्थिक और तकनीकी आकांक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त,लैटिन अमेरिका कृषि उत्पादों,फार्मास्यूटिकल्स और उभरते बाजारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत की दवा उद्योग और आईटी सेवाएँ इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ रखती हैं। यदि भारत अपनी कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को सशक्त करता है, तो वह चीन की बढ़ती पकड़ को संतुलित कर सकता है जिसने हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश और अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी लैटिन अमेरिका भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत को स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यता जैसी आकांक्षाओं के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। लैटिन अमेरिकी देशों का समर्थन इस दिशा में निर्णायक हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत केवल संकट के समय प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करे।

भारत को अपनी लैटिन अमेरिका नीति में बदलाव करते हुए अधिक सक्रिय,बहुआयामी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें नियमित उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद,व्यापार और निवेश समझौते,सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विकास सहयोग शामिल होना चाहिए। साथ ही,भारत को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह किसी भी क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्रों की राजनीति का समर्थन नहीं करता, बल्कि संप्रभुता,समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित संबंधों का पक्षधर है।

अंततः,वेनेजुएला संकट और मुनरो सिद्धांत की संभावित वापसी केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों का प्रतीक है। भारत का संतुलित रुख इस बात का संकेत है कि वह न तो अंधानुकरण करना चाहता है और न ही अनावश्यक टकराव। यह रुख उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच, वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता और बहध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थन को दर्शाता है। आने वाले समय में यदि भारत लैटिन अमेरिका के प्रति अधिक सक्रिय और दूरदर्शी नीति अपनाता है,तो वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुदृढ़ करेगा,बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान दे सकेगा।

मकर संक्रांति और पोंगल

सुभाष बुड़ावन वाला,
रतलाम,मध्यप्रदेश

मकर संक्रांति और पोंगल भारत की उस कृषि परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं, जहाँ प्रकृति,परिश्रम और अध्यात्म एक-दूसरे में घुलकर जीवन को उत्सव बना देते हैं। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है,क्योंकि इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है और प्रकाश, ऊर्जा व सकारात्मकता में वृद्धि मानी जाती है।

यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य,तिल-गुड़ के सेवन

और यज्ञ-हवन की परंपरा प्रचलित है। तिल को ऊर्जा और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना गया है,जिससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में स्वास्थ्य और आपसी संबंधों में मिठास बनी रहे। देश के विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग-अलग नामों और रूपों में मनाया जाता है—कहीं पतंग उत्सव के रूप में, तो कहीं नए अन्न के स्वागत के रूप में। इसी क्रम में दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला पोंगल पर्व विशेष रूप से तमिल संस्कृति से जुड़ा है, जो चार दिनों तक चलता है और सूर्य, प्रकृति, पशुधन तथा परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।

पोंगल का मुख्य आकर्षण मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ से बना प्रसाद है, जिसे खुले आंगन में सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है; जब दूध उफनता है तो उसे समृद्धि और शुभ संकेत माना जाता है। पहले दिन भोगी पर पुराने वस्त्रों और अनुपयोगी वस्तुओं को त्यागकर नए जीवन की शुरुआत का संदेश दिया जाता है,दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल में गाय-बैलों को सजाकर सम्मानित किया जाता है,और चौथे दिन कनुम पोंगल सामाजिक मेल-मिलाप का उत्सव बनता है। आधुनिक समय में इन पर्वों का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है,क्योंकि ये हमें प्रकृति-संतुलन, जैविक खेती, स्थानीय अन्न के उपयोग और सामुदायिक जीवन की महत्ता की याद दिलाते हैं।

इस्कॉन जैसे आध्यात्मिक संगठनों में इन अवसरों पर हरिनाम संकीर्तन,अन्नदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा और भक्ति को जोड़ा जाता है,जिससे उत्सव केवल परंपरा नहीं, बल्कि करुणा और चेतना का माध्यम बन जाता है। मकर संक्रांति और पोंगल हमें सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक नहीं,बल्कि कृतज्ञ हृदय,साझा आनंद और प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित है।

कविता

जनावतथे अबड़ सरगुजा कर जाड़ा

संतोष सरल,
अंबिकापुर,
सरगुजा,
छत्तीसगढ़

जनावतथे अबड़ सरगुजा कर जाड़ा।
गोरसी ला बारा दाऊ कांपतथे हाड़ा।

1

ए जीव हर सांय सांय करतथे मितान।
जाड़ रोसाही त नई बांचे ककरो परान।
नाक कान ला ढांऐक लेईहा गोई हो,
चुरईहा आदी गोल मरीच कर काढ़ा।
जनावतथे अबड़ सरगुजा कर जाड़ा।
गोरसी ला बारा दाऊ कांपतथे हाड़ा।

2

भिनसरिहा उठे वला रज़ाई भीतरी अहंय।
सबेरे बुले वला आगी धरि बईठीन अहंय।
अंधेरिया निकले वला काबर तो ऐदे,
नई भेंटाएं दरूहा काका अऊ बाड़ा।
जनावतथे अबड़ सरगुजा कर जाड़ा।
गोरसी ला बारा दाऊ कांपतथे हाड़ा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

भारतीय कूटनीति की परीक्षा का समय

शिवकांत शर्मा

कहने को तो एक साल ही बदला है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी उथल-पुथल मचाई है, उससे लगता है मानो एक युग बदल गया है। नए साल की शुरुआत में ही उन्होंने वेनेजुएला पर धावा बोल दिया। अमेरिका इस वर्ष अपनी स्थापना की 250 वीं जयंती मनाएगा,लेकिन दुनिया के सबसे उदार,संतुलित और स्थिर लोकतंत्र के संस्थापकों ने क्या कभी सोचा होगा कि कोई राष्ट्रपति 250 वर्षों से स्थापित व्यवस्था को केवल एक साल के भीतर उलट-पलट देगा? अफ्रीकी मूल के फंक गायक जेम्स ब्राउन का मशहूर गीत है- इट्स मेंस वर्ल्ड (यह मर्दों की दुनिया है)। उसी तर्ज पर कहा जा सकता है कि यह ट्रंप की दुनिया है-खासकर भूराजनीति और अर्थनीति के मामले में।

ट्रंप की दुनिया में किसी स्थापित कूटनीतिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय कायदे-कानून की कोई गारंटी नहीं है। यह द्वितीय महायुद्ध के बाद बनी नियमबद्ध व्यवस्था वाली दुनिया से नितांत भिन्न है,जिसके आधार पर भारत की विदेश और व्यापार नीति टिकी है। जिस गुटबाजी से भारत को परहेज था,वह सोवियत संघ के विघटन से टूटी और दुनिया एकध्रुवीय बन गई। भारत ने गुटनिरपेक्षता की जगह हितसापेक्ष स्वायत्तता की नीति अपनाई और खेमेबाजी से दूर रहते हुए अपनी सामरिक एवं आर्थिक शक्ति के विकास के लिए अमेरिका का रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार बन गया।

भारत से पहले चीन ने भी गुटबाजी छोड़कर अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ व्यापारिक साझेदारी की,जिसकी बदौलत आज वह अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। ट्रंप खुद चीन को जी-2 का दूसरा जी यानी दूसरी महाशक्ति मान चुके हैं। रूस को वे सामरिक महाशक्ति मानते हैं, लेकिन वह वैश्विक शक्ति संतुलन की तीसरी धुरी बनने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे चीन के खेमे में पहुंचा दिया है। यानी दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बंटती दिख रही है, जबकि भारत बहुपक्षीय व्यवस्था चाहता है। ट्रंप के

यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु संधि जैसी वैश्विक संस्थाओं और संधियों से हाथ खींच लेने के कारण उभरती शक्तियों के लिए विश्व मंच पर कुछ जगह जरूर बनी है। हालांकि नियमबद्ध व्यवस्था का स्थान महाशक्तियों की मनमानी ने ले लिया है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाना, ईरान और नाइजीरिया पर हवाई हमले और ताइवान को डराने के लिए चीन के सैनिक अभ्यास इसके ताजा उदाहरण हैं।

महाशक्तियों की मनमानी भारत के लिए चिंताजनक है। भारत चाहता जरूर है कि वैश्विक संस्थाएं अमेरिका और यूरोप के नियंत्रण से मुक्त हों,पर नियमबद्धता की कीमत पर नहीं। वह चाहता है कि वैश्विक संस्थाओं में भारत,ब्राजील,दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसी शक्तियों को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले। महाशक्तियों की मनमानी वाली अव्यवस्था में यदि भारत को सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में उचित स्थान मिल भी जाए तो उसकी व्यावहारिक उपादेयता क्या रह जाएगी? हकीकत यह है कि भारत को इसी व्यवस्था के भीतर अपनी विदेश नीति के कौशल से अपनी जगह बनानी है। इस साल उसे ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करनी है, जहां उसे दक्षिणी देशों का नेतृत्व करने का अवसर तो मिलेगा,मगर उसके लिए उसे चीन का सामना भी करना पड़ेगा। ब्रिक्स का सदस्य ईरान भी है, जहां मुद्रा के अवमूल्यन और आर्थिक संकट को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि प्रदर्शनों पर सख्ती बरती गई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अध्यक्ष होने के नाते ब्रिक्स देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की यह धमकी भारत के लिए यूक्रेन जैसा धर्मसंकट खड़ा कर सकती है।

भारत को एक साल से टलती आ रही क्वाड शिखर बैठक का आयोजन भी करना है,जो ट्रंप की भारत यात्रा पर निर्भर करेगा। ट्रंप की भारत यात्रा व्यापार वार्ताओं की प्रगति पर निर्भर करेगी, जिनके सिरे न चढ़ने के कारण 25 साल पुराने संबंधों में खटास आई है। हालांकि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियर ने भारत के प्रस्तावों को अब तक मिले सर्वश्रेष्ठ व्यापार प्रस्ताव बताया है, पर ट्रंप के रवैये को देखते हुए भारत किसी बात पर भरोसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे अमेरिकी बाजार के विकल्प खोजने ही होंगे। उसने यूएई,ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए हैं,लेकिन अमेरिकी बाजार के जाने से हुए नुकसान की भरपाई इनसे नहीं केवल यूरोप और खाड़ी परिषद के व्यापार समझौतों से ही हो सकती है और वह भी कुछ हद तक। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डे लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा की गणतंत्र दिवस पर भारत यात्रा से उम्मीद है कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिल सकेगा।

अवैध कब्जे और बेघर होता भारतः एक अंतहीन राष्ट्रीय संकट

ललित गर्ग
पटपड़गंज, दिल्ली-92

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है,जो शहरीकरण,पलायन, राजनीतिक स्वार्थप्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है। देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान,दुकानें, झुग्गियां,गोदाम,यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है। जब अचानक विकास परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, रेलवे, मेट्रो, औद्योगिक गलियारों या स्मार्ट सिटी योजनाओं की जरूरत सामने आती है, तब सरकार की नींद खुलती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर टूटता है, जो वर्षों से वहां रह रहे होते हैं और जिनका जीवन,आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य उसी जमीन से जुड़ चुका होता है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क जैसे संगठनों के आंकड़े इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। वर्ष 2017 से 2023 के बीच साढ़े तीन लाख से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाए गए और करीब सोलह लाख लोग बेघर हुए। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में लगभग 1.7 करोड़ लोग ऐसे दायरे में हैं, जिनके घर विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण टूट सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए,बच्चों को स्कूल में डाला,आसपास रोजगार तलाशा और एक स्थायी जीवन की कल्पना की। जब ये घर टूटते हैं तो केवल दीवारें नहीं गिरतीं,बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक संरचना ढह जाती है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रायः एक आवश्यक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है,लेकिन इसके मानवीय पक्ष को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बेघर होना केवल सिर से छत छिनने की समस्या नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य,सुरक्षा,सम्मान और भविष्य की संभावनाओं पर सीधा प्रहार है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है,महिलाएं असुरक्षा और अस्थिरता के भय में जीने लगती हैं,बुजुर्ग इलाज और सहारे से वंचित हो जाते हैं और पुरुष वर्ग बेरोजगारी तथा मानसिक तनाव से जूझने लगता है। पुनर्वास योजनाएं कागजों पर तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वे या तो अधूरी होती हैं या इतनी दूरस्थ जगहों पर लागू की जाती हैं कि वहां रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। इस पूरी समस्या का एक के वा सच यह भी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक दिन या एक रात में नहीं हो जाता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है,जिसमें प्रशासनिक उदासीनता, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण की बड़ी भूमिका होती है। जब गांवों से पलायन कर गरीब परिवार शहरों की ओर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सस्ती या खाली जमीन की तलाश होती है। सरकारी जमीन इस दृष्टि से सबसे आसान निशाना बनती है। पहले अस्थायी झोपड़ियां खड़ी होती हैं,फिर धीरे-धीरे पक्के मकान,दुकानें और अन्य निर्माण होने लगते हैं। सरकारी एजेंसियां एवं जिम्मेदार तो तब ही हरकत में आते हैं जब या तो कोई हादसा होता है या फिर विकास कार्यों के दौर में इन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है। महज सात साल में 16 लाख लोगों के बेघर होने का आंके ा छोटा नहीं है। इनमें भी 58 प्रतिशत से ज्यादा के बेघर होने की वजह अतिक्रमण ही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की मिलीभगत से अनदेखी होती है,यह भी किसी से छिपा नहीं है। बिजली,पानी,राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी सुविधाएं भी किसी न किसी रास्ते से मिल जाती हैं, जिससे यह अतिक्रमण धीरे-धीरे 'वैधता' का भ्रम पैदा करने लगता है।

इस पूरी प्रक्रिया में भू-माफिया की भूमिका भी बेहद खतरनाक है। वे सरकारी जमीनों की पहचान कर गरीबों को वहां बसाते हैं,उनसे पैसे वसूलते हैं और बाद में राजनीतिक संरक्षण के जरिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। चुनाव आते ही ये बस्तियां वोट बैंक में बदल जाती हैं। इस राजनीतिक खेल में न तो कानून की प्रतिष्ठा बचती है और न ही आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहता है। अतिक्रमण हटाने के बाद होने वाले नुकसान को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो यह केवल प्रभावित परिवारों का नुकसान नहीं,बल्कि पूरे देश का नुकसान है। एक ओर लोग अपने सीमित संसाधनों से घर बनाते हैं, दूसरी ओर सरकार अतिक्रमण हटाने पर भारी खर्च करती है। यदि शुरुआत में ही सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, समय पर निगरानी हो और अवैध कब्जे को बे ने से रोका जाए,तो यह दोहरा नुकसान टाला जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां किसी परियोजना की घोषणा और उसके क्रियान्वयन के बीच लंबा अंतराल रहता है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठाते हैं। वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रहती है और देखते ही देखते वहां एक पूरी बस्ती खड़ी हो जाती है।

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम गांवों की तस्वीर और तक़दीर बदलेगा: राजेश अग्रवाल

मनरेगा से अधिक पारदर्शी,प्रभावी और रोजगार बढ़ाने वाला कानून

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार को संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है,जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कोरिया जिला प्रभारी ललन प्रताप सिंह,जिलापंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह,महामंत्री द्वय विनोद हर्ष एवं अरुणा सिंह, जिला संवाद प्रमुख रुपेश दुबे की उपस्थिति प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह अधिनियम किसानों,मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय,आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था,वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।

इससे रूकेगा पलायन

राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे,ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।

पूर्व में मिलती थी कई शिकायतें

मंत्री ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल,मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं,जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा–जल सुरक्षा,ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार,कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि,पशुपालन,मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

जनजागरूकता अभियान,बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर दें विशेष ध्यान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

विजन समाजसेवी संस्था द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थानों,स्कूलों,महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और विधिक अधिकारों की जागरूकता हेतु जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दो महीनों में संस्था द्वारा दर्जन भर से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों को मानसिक अवसाद से बचाने और उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि जीवन अनमोल है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं, ताकि वे जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें।

हाल ही में राजपुरी बालिका कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और दशमेश पब्लिक स्कूल में 'जीवन अनमोल है' थीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ समाजसेवी और साहित्यकार संतोष दास जी ने कहा कि बच्चों और युवाओं में बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं ने पूरे समाज को चिंतित कर दिया है। उन्होंने इस पर ध्यान देने और बच्चों के लिए संवेदनशील कदम उठाने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम की सूत्रधार समाजसेविका और अधिवक्ता शिल्पा पांडे सृष्टि ने बताया कि अब तक संस्था द्वारा सरगुजा जिले में 15 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें लगभग बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। संस्था बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करती है, ताकि वे अपने विचार और समस्याएं बिना किसी डर के साझा कर सकें। शिल्पा पांडे ने यह भी बताया कि बच्चों द्वारा लिखित समस्याओं का समाधान बिना उनकी पहचान उजागर किए किया जाता है, ताकि उनका मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सके। कार्यक्रम में महिला थाने की प्रभारी सुनीता भारद्वाज का भी विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा,पुलिस विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति,साइबर अपराध और मोबाइल के दुरुपयोग पर भी जनजागरूकता फैलाई गई। राजपुरी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्रावास अधीक्षक अनुराधा सिंह ने भी मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मीडिया प्रभारी राजू यादव ने बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रहने के लिए जागरूक किया और इसके खतरों के बारे में बताया।

स्कूटी से अनियंत्रित होकर नहर में गिरे युवक की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

स्कूटी से अनियंत्रित होकर नहर में गिरे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम भालुकछार का कपिलेश कुमार सिंह पिता तिलेश्वर सिंह 37 वर्ष, 6 जनवरी को शाम करीब 6 बजे स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 15 सीएम 2437 में घूमने के लिए निकला था। शाम करीब 7.30 बजे गांव के दिनेश यादव ने मोबाइल फोन से सूचना दिया कि उनका लडक़ा घुनघुट्ठा बांध के पास नहर में गिर गया है। इसकी सूचना मिलने पर कपिलेश मौके पर पहुंचे तो उनके लडक़े को पानी के अंदर से निकालकर मेड़ पर रखे थे। युवक का शरीर गर्म था, लेकिन सांस नहीं चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर डॉयल 112 वाहन के साथ टीम मौके पर पहुंची और युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के आपातकालीन चिकित्सा परिसर में लेकर स्वजन पहुंचे, यहां रात 9.20 बजे जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

अत्यधिक रक्तस्राव से महिला की मौत,पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना क्षेत्र की एक विवाहिता अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इलाज के बीच दम तोड़ दी। पुलिस ने मौत का कारण स्पष्ट करने के लिए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के मुताबिक मृतका कलेश्वरी राजवाड़े पति राकेश राजवाड़े 34 वर्ष, सूरजपुर जिला के रामानुजनगर थाना अंतर्गत ग्राम की रहने वाली थी। मृतका के पति ने पुलिस को बताया है कि एक जनवरी को मासिक रक्तस्राव हुआ था,जो ज्यादा ही बढ़ गया। पत्नी ने बताया कि रक्तस्राव नहीं रूक रहा है, और काफी कमजोरी लग रहा है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को सूरजपुर के बीएल मेमोरियल मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल ले गया था। यहां इलाज के बाद रक्तस्राव कुछ कम हुआ, और शारीरिक कमजोरी को देखते हुए अतिरिक्त ब्लड चढ़ाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 6 जनवरी को चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया था। 7 जनवरी को अलसुबह महिला को लेकर उसका पति मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचा,यहां इलाज के दौरान दोपहर उसकी मौत हो गई। ऐसे में अत्यधिक रक्तस्राव होने से आई शारीरिक कमजोरी के कारण महिला के मौत की संभावना स्वजन व्यक्त कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

पति भाग गया दूसरी लडकी लेकर पत्नी आत्महत्या कर दी जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

शादी के बाद बच्चे नहीं होने पर पति दूसरी लडक़ी को लेकर भाग गया। इस तनाव को विवाहिता झेल नहीं पाई और चूहा मार दवा का सेवन करके जान दे दी। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बरियो निवासी मृतिका के चाचा ससुर महेन्द्र सोनवानी पिता रामरतन सोनवानी ने पुलिस को बताया कि संजय सोनवानी का शादी वर्ष 2009 में ग्राम मानपुर चैकी खडग़वां थाना प्रतापपुर निवासी अमृत कुंवर सोनवानी से सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। दोनों के दामपत्य जीवन के बीच कोई संतान नहीं है। 5 जनवरी को अलसुबह करीब 5 बजे संजय सोनवानी के घर की ओर शोर सुनकर जब वे संजय के यहां गए तो भीड़ लगा था, उसकी पत्नी अमृत कुंवर रो रही थी। पूछताछ करने पर चाची सास कपालो बताई कि अमृत कुंवर घर को अंदर से बंद कर ली थी और चूहा मारने वाला दवाई व कुछ टेबलेट को खा ली है। किसी तरह दरवाजा तोडक़र उसे बाहर निकाले हैं। उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल अंबिकापुर ला रहे थे, इस दौरान रास्ते में अमृत कुंवर बताई कि उसका पति संजय दूसरी लडक़ी को लेकर भाग गया है, अब घर नहीं आएगा। ऐसे में मृतका के पति के द्वारा दूसरी लडक़ी लेकर भागने से तनाव में आकर चूहा मारने की दवा सेवन करने की संभावना चाचा ससुर ने व्यक्त की है।

मतदाताओं के नाम विलोपित होने पर टीएस सिंहदेव ने जताई चिंता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनिरिक्षण को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में पांचवी समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसआईआर को लेकर नियुक्त प्रभारियों के साथ ही कांग्रेस के सभी सांगठनिक ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक दल विशेष द्वारा हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी बूथ पर कांग्रेस के 50 वोट कटवाने के साथ ही अपने 50 अतिरिक्त वोट समायोजित करने के निर्देश दिये हैं। संभवतः इस कार्य में लगे अधिकारियों को भी इस बाबत् अनौपचारिक निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके प्रति सतर्कता बरतनी है। उन्होंने बूथलेबल एजेंट को यह सलाह जारी किया है कि वे अपने बूथों पर बीएलओ से तालमेल कर दैनिक आधार पर आने वाली ऐसी सूचि का अवलोकन कर इस कवायद पर नजर रखें एवं ऐसी अनियमितताओं से जिला संगठन को तत्काल अवगत कराएं ताकि इसके विरुद्ध त्वरित कारवाई की जा सके। उन्होंने जिला संगठन के साथ ही ब्लॉक कार्यकारणी और मंडल कार्यकारणी के सभी सदस्यों को तत्काल उनके बूथ पर बीएलए के साथ नियुक्त कर कार्य सम्हालने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उन्होंने पूरे जिले में नवगठित 94 बूथ पर तत्काल बीएलए नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

मसौदा सूचि में बडी संख्या में मतदाताओं के नाम विलोपित होने पर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों के वितरण के समय प्रशासन के द्वारा जारी आंकडों में 99 प्रतिशत गणना प्रपत्रों को वितरित बताया गया था, लेकिन मसौदा सूचि जारी होने पर बडी संख्या में अनुपस्थित और अनमैप्ड कैटेगरी में मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया जो इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न खडा कर रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि दावा आपत्ती के अंतिम 15 दिन के दौर में कांग्रेस के सभी बीएलए के साथ ही संबंधित बूथ के कार्यकर्ता आम मतदाता के हित में सजग और सतर्कता के साथ कार्य करें। बैठक के संयोजन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अगामी 2 दिनो के अंदर बूथ स्तर पर कार्यकारणी सदस्यों की नियुक्ती कर उनकी सूचि भेजने का निर्देश दिया। बैठक को अम्बिकापुर विधानसभा प्रभारी अजय अग्रवाल, लुंड्रा विधानसभा प्रभारी सोमेश्वर सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, जेपी श्रीवास्तव, विक्रमादित्य सिंहदेव, राजीव सिंह, हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा, राजनाथ सिंह, बलराम यादव, मो इस्लाम आदि उपस्थित थे।

सरपंच संघ ने खोला मोर्चा...11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने 11 सूत्री मांग पत्र के साथ मोर्चा खोला। सरपंच संघ के सदस्य बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सरपंच संघ का प्रमुख मांग पत्र में कहा गया कि सभी ग्राम पंचायतों को 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों का एजेंसी बनाया जाए, ग्राम पंचायतों के बजट को 15वीं और 16वीं वित्त की राशि तत्काल जारी की जाए, धरती आबा योजना को पूरे ग्राम पंचायतों में लागू किया जाए, सरपंचों का मानदेय राशि 15,000 रुपये, पेंशन 5,000 रुपये और पंचों का मानदेय 2,000 रुपये किया जाए,ग्राम पंचायतों को मिलने वाली मूलभूत राशि 5 लाख रुपये की जाए,सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए,15वीं और 16वीं वित्त की राशि को टाईड और अनटाईड मद में समान किया जाए ताकि ग्राम पंचायत सर्वसहमति से कार्य करा सके, सभी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया जाए, मनरेगा योजना के तहत 60/40 के रेसियो को हर ग्राम पंचायत में लेबर और सामग्री के बजट में जारी किया जाए, आवारा मवेशियों के संरक्षण के लिए गौठान का पुनः निर्माण किया जाए और इसके देख-रेख के लिए दो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए व सरपंच संघ के जिला में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। सरपंच संघ ने इन 11 सूत्री मांगों के माध्यम से पंचायतों के विकास और सरपंचों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता जताई है। यह मोर्चा स्थानीय पंचायतों की दशा और दिशा को सुधारने के उद्देश्य से खोला गया है।

भाजपा के आधार स्तंभ स्व. लरंग साय को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि

जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में लरंग साय चौक पर हुआ माल्यार्पण,उनके योगदान को किया गया स्मरण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

भाजपा सरगुजा के वरिष्ठ नेता,पूर्व सांसद एवं पार्टी के आधार स्तंभ स्वर्गीय लरंग साय की पुण्यतिथि पर जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में भाजपा सरगुजा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने लरंग साय चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्व. लरंग साय के योगदान और जीवनी को स्मरण करते हुए जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि लरंग साय केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि सरगुजा की आदिवासी चेतना और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने सादगी, संघर्ष और सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाकर राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया। उनका जीवन आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि लरंग साय शुरू में शिक्षक थे, लेकिन बाद में भारतीय जन संघ (जो बाद में भाजपा का हिस्सा बनी) से जुड़ गए। उन्होंने जन संघ के टिकट पर 1967 में पहली बार सामरी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक पद संभाला। उन्होंने बताया कि वे 1967-1977 – सामरी विधानसभा से विधायक , 1980-1985 – फिर से सामरी से विधायक,1977-1980 – पहली बार सांसद, जन लोक दल के रूप में जीते, 1989-1991 – भाजपा से सांसद,1998-1999 – पुनः भाजपा से सांसद तथा वे केंद्रीय श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे 14 अगस्त 1977 से 28 जुलाई 1979 तक – तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरामजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में रहे। श्री सिसोदिया ने कहा लरंग साय को सरगुजा और आस-पास के आदिवासी इलाकों में जनप्रिय नेता और आदिवासी सहित सभी वर्ग हितैषी के रूप में जाना जाता था।

जिले में विज्ञान,गणित एवं प्रौद्योगिकी आधारित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा इसरो भ्रमण का अवसर : कलेक्टर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले में विद्यार्थियों के सर्वांगीण बौद्धिक विकास,वैज्ञानिक दृष्टि कोण के विस्तार तथा गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान,गणित एवं प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों पर केंद्रित एक भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में लोकप्रिय विज्ञान वार्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मॉडल प्रदर्शनी (स्थिर एवं कार्यशील),विज्ञान एवं गणित आधारित निबंध लेखन, सेमिनार प्रतियोगिता,विज्ञान के साथ मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ तथा जन-जागरूकता अभियान जैसी विविध गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया,जिसने विद्यार्थियों सहित उपस्थित सभी अतिथियों को गहराई से प्रभावित किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में जिला समन्वयक श्रीमती लीना थॉमस सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी,समिति सदस्य, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी का युग है तथा नवाचार ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर प्रयोग, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से अपने विचारों को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने स्टार्टअप संस्कृति को अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि विद्यार्थी नई सोच के साथ समाज की समस्याओं के समाधान खोजें। कलेक्टर श्री वसंत ने घोषणा की कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्य करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में श्रीहरिकोटा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भ्रमण का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा जी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता,बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को कठिनाइयों को सीखने के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा दी तथा शिक्षकों से विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तर्कशक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया।

निधन

मनेंद्रगढ़ ओसवाल समाज की वरिष्ठ,धर्मपरायण एवं श्रद्धेय मातृशक्ति स्व. श्रीमती सूरज देवी चोपड़ा (उम्र लगभग 88 वर्ष) का सोमवार, 5 जनवरी 2026 को स्वर्गवास हो गया। आप स्व. गणेशमल चोपड़ा की धर्मपत्नी एवं राजेंद्र चोपड़ा (पवन) की पूज्य माताजी थीं। मंगलवार को आत्मीय परिजनों की उपस्थिति में मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात ओसवाल भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि सभा में व्यापार संघ के संरक्षक रतन कुमार (मामा), शांतिलाल बोथरा, मूलचंद दुगड़ सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं स्वजन उपस्थित रहे, ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।**ओम शांति।...**

बैंक नहीं...कर्ज का जाल! रिश्वत,फर्जी साइन और सूदखोरी का संगठित खेल,यूको बैंक बैकुंठपुर की शाखा पर गंभीर आरोप

- 18-22 साल के युवाओं को कर्ज़ में धकेला गया, यूको बैंक मैनेजर-भाई की जोड़ी पर गंभीर आरोप
- फर्जी हस्ताक्षर से लोन,चेक बाउंस की सूचना रोकी गईः यूको बैंक शाखा प्रबंधक पर जांच की मांग...

जहाँ भरोसा होना था, वहीं वसूली चली, यूको बैंक बैकुंठपुर कटघरे में

दोस्ती का झांसा, लोन का फंदाः यूको बैंक में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

सार्वजनिक बैंक में निजी सूदखोरी? यूको बैंक बैकुंठपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल

फाइल फोटो

फाइल फोटो

-जिला प्रतिनिधि-

बैकुंठपुर,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिस बैंक पर जनता की गाढ़ी कमाई और भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही बैंक यदि युवाओं को जबरन कर्ज में फंसाने, रिश्वत लेकर लोन बांटने,फर्जी हस्ताक्षरों से ऋण स्वीकृत कराने और सूदखोरी के धंधे का माध्यम बन जाए,तो यह केवल अनियमितता नहीं,बल्कि संगठित वित्तीय अपराध का संकेत है,यूको बैंक की बैकुंठपुर शाखा पर लगे आरोप ठीक इसी भयावह तस्वीर को उजागर करते हैं। शहर की यूको बैंक शाखा बैकुंठपुर इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है,शाखा प्रबंधक और उनके भाई पर युवाओं को कथित तौर पर रिश्वत लेकर लोन में फंसाने,फर्जी हस्ताक्षरों से ऋण स्वीकृत कराने,चेक बाउंस की सूचना रोकने और सूदखोरी के लिए बैंक तंत्र के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों के सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था, ग्राहकों की गोपनीयता और युवाओं की आर्थिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं,अब यह मामला केवल आरोप बनाम आरोप नहीं रहा,कानूनी नोटिस जैसे आधिकारिक दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि युवाओं को पहले आर्थिक जाल में फंसाया गया,फिर कानूनी डर दिखाकर दबाया गया, यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई,तो यह प्रकरण सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था पर गहरा दाग बन सकता है।

दस्तावेज-1 : पहला कानूनी नोटिस (दिनांक 25 अक्टूबर 2025)

यूको बैंक शाखा प्रबंधक के भाई के अधिवक्ताः मुकेश कुमार के पहले नोटिस में निम्न तथ्य दर्ज हैं नोटिस के प्रमुख बिंदु के अनुसार अगस्त 2025 में ?18,17,000 (अठारह लाख सत्रह हजार) को 'फ्रेंडली लोन' बताया गया यह राशि निजी उपयोग हेतु लेने का उल्लेख 6 माह में भुगतान का समझौता अंतिम तिथि 18.08.2025 बताई गई, आंशिक भुगतान के नाम पर 6,00,000 का चेक दिनांक 07.10.2025 एचडीएफसी बैंक पर ड्रॉ यह चेक 09.10.2025 को खाते में पैसा नहीं होने कारण से बाउंस बताया गया 15 दिन में भुगतान नहीं होने पर आपराधिक कार्यवाही (एनआई एक्ट 138) की धमकी दी गई, महत्वपूर्ण तथ्य यह नोटिस स्पष्ट करता है कि लेन-देन को बैंकिंग लोन नहीं, बल्कि 'फ्रेंडली लोन' बताया गया, जबकि यह मामला उसी युवक से जुड़ा है जिसके खाते, लोन और बैंक गतिविधियां यूको बैंक बैकुंठपुर से जुड़ी बताई जा रही हैं।

यूको बैंक बैकुंठपुर प्रकरणः कानूनी नोटिसों से खुला लोन-चेक-सूदखोरी का पूरा खेल-

यूको बैंक बैकुंठपुर शाखा से जुड़े कथित लोन घोटाले, युवाओं को कर्ज में फंसाने और बैंकिंग तंत्र के दुरुपयोग के मामले में अब ठोस दस्तावेज सामने आ चुके हैं, पीड़ित युवक के विरुद्ध भेजे गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट,1881 की धारा 138(बी) के तहत दो कानूनी नोटिस इस पूरे प्रकरण को केवल आरोप नहीं,बल्कि दस्तावेजी सच्चाई में बदल देते हैं,ये नोटिस यह संकेत देते हैं कि कैसे पहले युवाओं को लोन/लेन-देन में उलझाया गया और बाद में चेक बाउंस व कानूनी दबाव के जरिये उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई।

दस्तावेज-2 : दूसरा कानूनी नोटिस (दिनांक 06 दिसंबर 2025)-

दूसरा नोटिस पहले से कहीं अधिक गंभीर और संदिग्ध परिस्थितियों को उजागर करता है, दूसरे नोटिस में नए तथ्य, पहले नोटिस (25.10.2025) के बाद युवक ने 'आगे कार्रवाई न करने' का अनुरोध किया, 16.11.2025 को मुलाकात का दावा, युवक द्वारा देयता स्वीकार करने की बात लिखी गई, इसके बाद पूरी विवादित राशि 18,17,000 का दूसरा चेक दिनांक 17.11.2025 फिर से एचडीएफसी बैंक पर ड्रॉ, यह चेक भी 18.11.2025 को पैसा नहीं होने के कारण से बाउंस अब पूरे 18,17,000 की मांग 15 दिन में भुगतान नहीं होने पर जेल और जुर्माने की चेतावनी।

टारगेट कर 'लोन फँसाओ' मॉडल-

सूत्रों और पीड़ितों के बयानों के अनुसार, शाखा से जिन ऋणों का वितरण हुआ, उनमें बड़ी संख्या 18 से 22 वर्ष के युवाओं की बताई जा रही है, आरोप है कि कई युवाओं को 'दोस्ती' और 'आसान लोन' का झांसा दिलाकर मुद्रा लोन और अन्य ऋण दिलाए गए, जबकि उनमें से कई न तो वास्तविक व्यवसाय कर रहे थे और न ही व्यापार से उनका कोई संबंध था, कई मामलों में युवाओं के परिवार तक को लोन की जानकारी नहीं थी, परिणामस्वरूप आज अनेक खाते एनपीए बनने की कगार पर हैं और युवा कर्ज के बोझ तले दब गए हैं।

फर्जी हस्ताक्षरः कानून का खुला मजाक : सबसे चौंकाने वाला आरोप एक मामले से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर लोन स्वीकृत कर दिया गया,जब संबंधित व्यक्ति ने विरोध किया, तो उसके खाते में 7 लाख डाल दिए गए, लेकिन 1 लाख आज भी बकाया बताया जा रहा है,जिससे लोन खाता बंद नहीं हो पा रहा, यही नहीं,आरोप है कि इस राशि में से 3 लाख एक वेंडर को दिए गए, जिसका संबंध कथित तौर पर ट्रैक्टर शोरूम संचालक के बेटे से बताया जा रहा है, यह पूरा लेन-देन बैंकिंग नियमों के उल्लंघन की आशंका पैदा करता है,यह क्या है अपराध छुपाने की कोशिश? पीड़ित को चुप कराने का तरीका या बैंकिंग रिकॉर्ड से खेल?

दस्तावेजों से निकलते बेहद गंभीर सवाल

सवाल नंबर 1. दो-दो चेक क्यों?
- जब 6 लाख का चेक पहले ही बाउंस हो गया था...
- तो पूरी राशि का दूसरा चेक क्यों लिया गया?

सवाल नंबर 2. बैंक सूचना क्यों नहीं?
- खाताधारक को न एसएमएस न कॉल न बैंक इंटीमेशन
- सीधे वकील का नोटिस — यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है।

सवाल नंबर 3. यूको बैंक और एचडीएफसी बैंक का संबंध?
- विवाद यूको बैंक बैकुंठपुर से जुड़ा लेकिन सभी चेक एचडीएफसी बैंक पर क्या यह जानबूझकर चुना गया रास्ता था?

सवाल नंबर 4. 'फ्रेंडली लोन' या सूदखोरी?
- लाखों की रकम, बार-बार चेक, कानूनी दबाव यह फ्रेंडली लोन नहीं, बल्कि संगठित वसूली मॉडल प्रतीत होता है।

यूको बैंक बैकुंठपुर से सीधा लिंक

पहले सामने आए आरोपों में कहा गया था कि युवाओं को यूको बैंक से मुद्रा लोन अन्य लोन जबरन दिलवाए गए,खातों की जानकारी का दुरुपयोग हुआ और बाद में निजी सूदखोरी के लिए चेक और नोटिस का सहारा लिया गया, अब ये कानूनी नोटिस उसी कहानी की दस्तावेजी कड़ी बनते दिख रहे हैं। अब जांच क्यों जरूरी हो गई है इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद निम्न बिंदुओं पर जांच अनिवार्य हो जाती है–

1. यूको बैंक बैकुंठपुर के सभी युवा खाताधारकों के लोन
2. चेक इश्यू की टाइमलाइन
3. बैंक से सूचना रोके जाने की भूमिका
4. बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों का गठजोड़
5. क्या बैंकिंग डेटा का उपयोग निजी वसूली में हुआ?

चेक बाउंस की सूचना रोकी गई?

कई खाताधारकों ने आरोप लगाया कि उनके खातों पर चेक प्रस्तुत होने और चेक बाउंस की जानकारी उन्हें न तो एसएमएस से मिली और न ही बैंक से फोन आया,जबकि सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में खाताधारक को पूर्व सूचना और कन्फर्मेशन दिया जाता है,एक पीड़ित के अनुसार, उसके दो चेक (एक 6 लाख और दूसरा लगभग 18.17 लाख) कथित तौर पर शाखा प्रबंधक के भाई के एचडीएफसी बैंक खाते में लगाए गए और बाउंस कराए गए,लेकिन खाताधारक को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई,सीधे वकील का नोटिस भेजा गया।

खाते में पैसा दिखते ही 'उधारी' का दबाव?

एक अन्य खाताधारक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शाखा प्रबंधक स्वयं खातों की निगरानी करते थे और खाते में पैसा दिखते ही उधारी मांगते थे 'कल लौटा देंगे, परसों लौटा देंगे,पैसा वापस न मिलने पर कई लोगों ने खाते में रकम रखना ही बंद कर दिया,यह आरोप सीधे तौर पर ग्राहक गोपनीयता और अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है, सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी शाखा प्रबंधक को हर खाताधारक का बैलेंस देखने और निजी उधारी मांगने का अधिकार है? यह आरोप ग्राहक गोपनीयता और अधिकारों के घोर उल्लंघन की ओर इशारा करता है। सवाल साफ है, क्या बैंक मैनेजर निजी उधारी के लिए खातों का इस्तेमाल कर सकता है?

सूदखोरी का धंधा, बैंक का चेक, खतरनाक गठजोड़

आरोप है कि शाखा प्रबंधक के भाई द्वारा चलाए जा रहे कथित सूदखोरी के धंधे में यूको बैंक के चेक का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैंक में भाई के प्रबंधकीय प्रभाव के चलते सूचनाएं और प्रक्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं, एक पीड़ित ने दावा किया कि उसे 6 लाख दिए गए,उसने 4 लाख लौटा दिए, फिर भी 18 लाख से अधिक के चेक लगाकर बाउंस कराए गए,यह वसूली नहीं, डर का कारोबार है।

नियमों पर सवाल,जांच की मांग तेज

बैंकिंग नियमों के अनुसार,चेक प्रस्तुत होने,बाउंस की स्थिति और खाते की गतिविधियों की जानकारी खाताधारक को दी जाती है, आरोप है कि इन मामलों में जानबूझकर सूचना रोकी गई,ताकि वसूली का दबाव बनाया जा सके,इन गंभीर आरोपों के बाद शाखा प्रबंधक और उनके भाई के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच, सभी लोन खातों की ऑडिट,सीसीटीवी व डिजिटल लॉग की फॉरेंसिक जांच, और पीड़ित युवाओं को राहत देने की मांग तेज हो गई है।

मरोसे पर वोट

स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां बैंक पर भरोसा होना चाहिए, वहीं अब 'रिश्वत और दबाव' की चर्चा आम हो गई है,यदि आरोप सही पाए जाते हैं,तो यह मामला केवल एक शाखा तक सीमित न रहकर पूरे बैंकिंग सिस्टम की साख पर सवाल खड़ा करेगा।

नियमों की धज्जियां,जवाबदेही कहाँ?

बैंकिंग नियम स्पष्ट हैं की चेक प्रस्तुत होने/बाउंस की सूचना, खाताधारक की पुष्टि, पारदर्शी क्रेडिट असेसमेंट,हितों का टकराव से बचाव यदि आरोप सही हैं,तो यह प्रणालीगत विफलता नहीं, जानबूझकर किया गया दुरुपयोग है, बैंक जनता का सहारा होता है,शोषण का औजार नहीं,यदि इन आरोपों पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठे,तो यह मामला केवल एक शाखा तक सीमित नहीं रहेगा,यह पूरे सार्वजनिक बैंकिंग सिस्टम की साख को चोट पहुँचाएगा।

मांगें: अब लीपापोती नहीं,कड़ी कार्रवाई स्थानीय नागरिकों और पीड़ितों की मांगें स्पष्ट हैं...

- स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच (बैंक से बाहर की एजेंसी)
- सभी लोन खातों का विशेष ऑडिट (पिछले वर्षों सहित)
- सीसीटीवी, कॉल लॉग,एसएमएस गेटवे,कोर बैंकिंग लॉग की फॉरेंसिक जांच
- हितों के टकराव पर तत्काल कार्रवाई
- पीड़ित युवाओं को राहत, दंडात्मक ब्याज/दबाव पर रोक
- दोष सिद्ध होने पर निलंबन,आपराधिक प्रकरण और रिकवरी

डिस्क्लेमर

यह रिपोर्ट पीड़ितों के बयानों, दस्तावेजों और सूत्रों पर आधारित आरोपों पर आधारित है,बैंक प्रबंधन/आरोपित पक्ष का पक्ष प्राप्त होते ही उसे समान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, यह रिपोर्ट उपलब्ध कानूनी दस्तावेजों और पीड़ित पक्ष के बयानों पर आधारित है,आरोपित पक्ष या बैंक प्रबंधन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री के गृह जिले में मातृ मृत्यु का सिलसिला जारी

22 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत...डेढ़ माह में चौथी घटना

-संवाददाता-

सूरजपुर,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। प्रसव सेवाओं के अभाव में 22 वर्षीय गर्भवती आदिवासी महिला की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि बीते डेढ़ महीने में जिले में यह चौथी मातृ मृत्यु है,जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार,सूरजपुर जिले के कोट गांव की रहने वाली 22 वर्षीय जगमनिया को प्रसव पीड़ा के दौरान अचानक गंभीर समस्या हो गई। परिजन उसे सूरजपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे,लेकिन वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण डॉक्टरों ने उसे तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रेफर किए जाने के दौरान ही महिला की हालत और बिगड़ती चली गई। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज शुरू किया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

लोगों ने लगाया यह गंभीर आरोप : स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल में प्रसव से जुड़ी उन्नत और आपातकालीन सुविधाओं का भारी अभाव है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को अंतिम समय में बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता है,जो कई बार जानलेवा साबित होता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि समय पर बेहतर इलाज की व्यवस्था होती, तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। यह मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का गृह जिला है। उनके द्वारा कई बार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधर पाए हैं।

पति से बातचीत पर महिला का रौद्र रूप,सड़क पर ही छात्रा से मारपीट,एक-दूसरे ने बाल खींचे-नाखून से खरोंचे..

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

सार्वजनिक जगह पर निजी विवाद कैसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकता है,इसका एक और उदाहरण छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले में सामने आया है। जनकपुर इलाके में बीच सड़क एक महिला और स्कूली छात्रा के बीच अचानक हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। छात्रा को सरेआम पीटे जाने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,विवाद के दौरान महिला और छात्रा के बीच झूमाझटकी हुई। महिला ने छात्रा के चेहरे पर नाखूनों से वार किया,जिससे उसके चेहरे पर कई

जगह खरोंच के निशान पड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों को अलग कराया,तब जाकर स्थिति शांत हुई। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया,जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से छात्रा की बातचीत से नाराज थी।

43 करोड़ की मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट

गिट्टी की जगह मिट्टी, फर्जी बिल, धमकियाँ और धूल जांच में उजागर हुआ बड़ा खेल

-संवाददाता-
एमसीबी/मनेन्द्रगढ़,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में शामिल मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी को जोड़ने वाली लगभग 43 करोड़ रुपये की बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजना इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और राहगीरों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, जहाँ मानकों के अनुसार गिट्टी (जीएसबी) डाली जानी थी,वहाँ मिट्टी और स्टोन डस्ट भर दी गई। साथ ही फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपये निकालने की कोशिश की जा रही है, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी सड़क परियोजना विकास की रीढ़ बन सकती थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और ठेकेदार की लापरवाही ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया है,अब देखना यह है कि प्रशासन सख्ती दिखाकर मानक निर्माण सुनिश्चित करता है या जनता को धूल,गड्ढों और टूटती सड़कों पर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

7 दिन बाद भी सुधार नहीं...

जांच के सात दिन बीत जाने के बावजूद ठेकेदार पर निर्देशों का असर नहीं दिख रहा। आरोप है कि रातों-रात फिर से मिट्टी भरकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अधिकारियों व जनता की आँखों में धूल झोंकी जा रही है।

सवाल जो प्रशासन से जवाब मांगते हैं...

जब वरिष्ठ अधिकारी गड़बड़ी पकड़ चुके हैं,तो सुधार में देरी क्यों?

बाहर के ठेकेदार अधिकारी मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई कैसे लूट पा रहे हैं?

क्या दोषियों पर वास्तविक कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा?

शिकायतों के बाद जांच,उखाड़ने के निर्देश

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद 31 दिसंबर को अंबिकापुर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। खुदाई के दौरान सामने आया कि जहाँ 4-5 फीट तक प्योर जीएसबी मटेरियल भरना अनिवार्य था, वहाँ ठेकेदार ने महज 1-1.5 फीट गिट्टी डालकर ऊपर से मिट्टी/डस्ट का मिश्रण भर दिया। जांच दल ने इसे घोर लापरवाही और धोखाधड़ी मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी सड़क को उखाड़कर फिर से मानक सामग्री से निर्माण किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो बिल भुगतान रोक दिया जाएगा और इंजीनियर व टाइमकीपर पर निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है।

'सेटिंग' और ट्रांसफर की धमकी के आरोप

स्थानीय सूत्रों के अनुसार,जांच के दौरान ठेकेदार अधिकारियों के सामने तो हामी भरता रहा, लेकिन बाद में मुख्य अभियंता को ट्रांसफर करा देने जैसी धमकियाँ देने की बातें सामने आईं, यह भी चर्चा है कि कमीशन को लेकर असहमति के बाद ही जांच तेज हुई। यदि ये आरोप सत्य हैं, तो यह न सिर्फ परियोजना बल्कि पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

धूल-प्रदूषण से जनता बेहाल-

निर्माण नियमों के मुताबिक धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी छिड़काव जरूरी है, लेकिन मौके पर इसका पालन नहीं मिला,मोटरसाइकिल,ऑटो और जीप से सफर करने वाले लोग धूल में घुटते नजर आए। इस पर निरीक्षण दल ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल छिड़काव के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने चेताया है कि हालात नहीं सुधरे तो वे एनजीटी में शिकायत दर्ज कराएंगे।

पुल पुलिया में भी घटिया काम

सड़क के साथ बन रही पुल-पुलियाओं में भी अनियमितताएँ मिलीं। 40 टन क्षमता की सड़क के लिए जहाँ एमपी-4 ग्रेड ह्यूम पाइप अनिवार्य हैं, वहाँ घटिया/टूटे पाइप लगाए गए। कई जगहों पर पाइप टूटे पाए गए,जिन्हें सीमेंट से ढककर नया दिखाने का प्रयास किया गया। जांच अधिकारियों ने साफ कहा कि मानक पाइप बदले जाएँ,अन्यथा भुगतान नहीं होगा।

पुराना रिकॉर्ड भी सवालों में

स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी ठेकेदार द्वारा पूर्व में बनाए गए कुछ पुल टूट चुके हैं,जिन्हें बाद में विभाग को दोबारा बनवाना पड़ा था। अब आरोप है कि पुराने पाइपों पर लेपन कर फर्जी बिल लगाने की कोशिश फिर से हो रही है।

लागत बनाम गुणवत्ता-

सूत्रों के मुताबिक,गुणवत्ता बनाए रखने के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर खर्च होने चाहिए,इसके बावजूद सामग्री में कटौती कर मुनाफा बटोरने की कोशिश सामने आई है। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है,बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।

नगर पालिक निगम कोरबा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा सवाल किया खड़ा

-संवाददाता-
कोरबा,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिक निगम कोरबा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा हैं की निगम की सामान्य सभा पिछले 7 महीनों से आयोजित नहीं किए जाने पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने इस मुद्दे पर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए नियमों की अनदेखी और जनहित की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दो माह में सामान्य सभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद 2 मई 2025 के बाद से एक भी सामान्य सभा नहीं बुलाई गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा है कि सामान्य सभा ही वह मंच है जहाँ शहर के विकास कार्यों, जनसमस्याओं और योजनाओं पर खुली चर्चा होती है। सभा न होने से पार्षदों के अधिकार बाधित हो रहे हैं, वहीं शहर के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अब तक 3 से 4 सामान्य सभाएं हो जानी चाहिए थीं, लेकिन एक भी बैठक न बुलाया जाना निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने निगम अध्यक्ष से तत्काल नियमों के अनुसार सामान्य सभा आयोजित करने के निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द बैठक नहीं बुलाई गई तो यह मामला और गंभीर राजनीतिक रूप ले सकता है।

सूरजपुर पुलिस ने ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को दिया प्रशिक्षण

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों,आपात प्रबंधन और जिम्मेदार ड्राइविंग पर जोर

-संवाददाता-
सूरजपुर,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,सोमवार, 05 जनवरी 2026 को स्टेडियम ग्राउंड सूरजपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के 65 ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों,सुरक्षित ड्राइविंग और आपात परिस्थितियों से निपटने संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, यह प्रशिक्षण डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना,दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना और यात्रियों के साथ-साथ चालकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।

यातायात नियमों का पालन अनिवार्य

कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के मार्गदर्शन में किया गया। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने चालकों को स्पष्ट रूप से बताया कि तेज गति से वाहन चलाना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है,नशे की हालत में ड्राइविंग पूर्णतः प्रतिबंधित है,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का उपयोग जानलेवा हो सकता है, वाहन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज (लाइसेंस,बीमा,रजिस्ट्रेशन) हमेशा साथ रखें।

सुरक्षा पोस्टर और शपथ-

प्रशिक्षण के दौरान चालकों के वाहनों में यातायात नियमों से संबंधित जागरूकता पोस्टर लगाए गए। साथ ही सभी चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने नियमों का पालन करने, यात्रियों या माल को क्षमता से अधिक न ढोने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी

यातायात पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने, ओवरलोडिंग, लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का मानना है कि ऑटो और ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन साधनों के चालक यदि जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, तो शहर में सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एएसआई ब्यासदेव राय, प्रधान आरक्षक मुरीस खाखा, आरक्षक प्रेमसागर साहू और बिलोन बड़ा सहित यातायात पुलिस का अमला उपस्थित रहा, सूरजपुर पुलिस का यह प्रयास न केवल चालकों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम है,बल्कि आम जनता के लिए यह संदेश भी है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून नहीं,बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है।

न्यायालय नजूल अधिकारी,अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0/.../अ-20 (3) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अखिलेश कुमार सोनी आ0 सुरेश प्रसाद सोनी, रत्ना सोनी पति अखिलेश कुमार सोनी दोनों निवासी महामाया चौक श्री कृष्ण ज्वेलर्स स्कूल रोड गुरूद्वारा वार्ड, अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-09 मोहल्ला स्कूल रोड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1169 / 9 रकबा 0.07,1/2 एकड़ भूमि को भारतीय स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा गुरूद्वारा काम्पलेक्स अम्बिकापुर में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-23/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है । नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-30/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202601020700025

विषय:-अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्:-2025-26

अंबिकापुर प.ह.न. 00015 [1633/16 (0.0240 हे0)]
पक्षकारों का विवरण:-
आवेदक पक्षकार- सतीश केशरी,
अनावेदक पक्षकार- राजेन्द प्रसाद,

ईश्तहार

आवेदक सतीश केशरी आ0स्व0 रजोन्द्र केसरी व अन्य निवासी मायापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1633/16 रकबा 0.024 हे0 भूमि के खातेदार राजेन्द्र प्रसाद केशरी का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30.01.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0 ./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिता गर्ग पत्नी राजेश गर्ग निवासी ब्रम्ह रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 484/95 रकबा 0.025 हे0 भूमि को अनावेदक आशीष असाटी आ0 कोमलचंद असाटी निवासी केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रूपये 15,50,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21.01.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा 7

आज दिनांक:-06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0 ./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कविता गर्ग पत्नी प्रदीप गर्ग निवासी ब्रम्ह रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 484/130 रकबा 0.025 हे0 भूमि को अनावेदक आशीष असाटी आ0 कोमलचंद असाटी निवासी केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रूपये 15,50,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21.01.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर, जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 ./अ-20(1)/24-25

ईश्तहार

आगामी तिथि 16/1/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक केदारनाथ मित्तल आ0 स्व. विलायती राम, निवासी वार्ड नम्बर 6 भैयाथान रोड सूरजपुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर सूरजपुर स्थित नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1863 / 4, 1864 / 2 रकबा क्रमषः 0.05, 0.01 - 1/2 डिसमिल भूमि का लीज अवधी 31.03.2026 को समाप्त होने से लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 16/1/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — नजूल अधिकारी सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नेहा सोनवानी आ0स्व. नान साय सोनवानी निवासी गांधीनगर थाना गांधीनगर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने पिता स्व0 नान साय सोनवानी आ0 स्व. मोहर साय सोनवानी की दिनांक 29/11/2024 को स्थान निवास में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 5/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर ,जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क्र01749 ./ब-121/2024
सूरजपुर,दिनांक 06/01/2026

आवेदक/आवेदक/ आवेदिका का नाम होस राम आ. स्व मानसाय जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीढ़ा पहन...तहसील सूरजपुर जिला (छ.ग.) ने अपने पिता स्व मान साय मृत्यु/जन्म दिनांक 01/01/2017 का मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/01/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में अपना स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

इस ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
उप तहसील मानी
तहसील सूरजपुर
सील — जिला सूरजपुर,छ0ग0

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर ,जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क्र01750./ब-121/2024
सूरजपुर,दिनांक 06/01/2026

आवेदक/आवेदिका का होस राम आ. स्व मानसाय जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीढ़ा पहन....तहसील सूरजपुर जिला (छ.ग.) ने अपने स्व रानियां मृत्यु/जन्म दिनांक 05/02/2021 का मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/01/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में अपना स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

इस ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
उप तहसील मानी
तहसील सूरजपुर
सील — जिला सूरजपुर,छ0ग0

न्यायालय तहसीलदार लटोरी ,जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 ./ब/121/वर्ष
ग्राम कल्याणपुर,प0ह0न0

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक परोजन आ0 वेशादू जाति गोड निवासी ग्राम कल्याणपुर रा0नि0म0 .... तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री अपने चाचा प0 देशू का जन्म/मृत्यु दिनांक 01/01/2025 को ग्राम कल्याणपुर में हुई है अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कल्याणपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं,अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 08/01/20 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 19-12-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
पेशी दिनांक - 08/1/2026
जारी दिनांक :-19/12/2025

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
तहसील लटोरी
सील — जिला-सूरजपुर,छ0ग0

CMYK

घुनघुट्टा रिसोर्ट किसके लिए...

नागरिकों के लिए या मैनेजर कुशवाहा के लिए?

- करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति पर 'निजी तानाशाही',पर्यटन विभाग और सरकार कटघरे में...
- सुकून की जगह या जनाक्रोश का केंद्र ? घुनघुट्टा रिसोर्ट में प्रबंधन की मनमानी से पर्यटक नाराज़
- रोक-टोक और अभद्र व्यवहार से बिगड़ी घुनघुट्टा रिसोर्ट की छवि,पर्यटन पर संकट
- प्रकृति तो सुंदर,व्यवस्था कठोर,घुनघुट्टा रिसोर्ट से पर्यटक मायूस
- ऊपर बात कर लीजिए' बना डरावना जवाब,घुनघुट्टा रिसोर्ट में बढ़ता आक्रोश
- पर्यटकों से बदसलूकी का आरोप,घुनघुट्टा रिसोर्ट को लेकर यूथ कांग्रेस का विरोध
- पर्यटन के नाम पर अघोषित पाबंदी ? घुनघुट्टा रिसोर्ट से सुकून गायब

-राजन पाण्डेय-

सोनहत,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

यह सवाल अब सिर्फ पर्यटकों की नाराजगी नहीं रहा,बल्कि जनहित और सार्वजनिक धन की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है, घुनघुट्टा रिसोर्ट आखिर किसके लिए बना है? क्या यह रिसोर्ट आम नागरिकों और पर्यटकों के सुकून के लिए है,या फिर एक मैनेजर की मनमानी और तानाशाही के लिए? सरकार ने सोनहत के घुनघुट्टा रिसोर्ट को करोड़ों रुपये की लागत से विकसित किया,यह पैसा जनता का पैसा है टैक्स और सार्वजनिक संसाधनों से,उद्देश्य साफ था पर्यटन को बढ़ावा,स्थानीय रोजगार, नागरिकों और पर्यटकों को प्रकृति के बीच सुकून लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट बताई जा रही है। बता दे की प्रकृति की गोद में बसे सोनहत के घुनघुट्टा रिसोर्ट की पहचान लंबे समय तक शांति, सुकून और हरियाली के लिए रही है, लेकिन बीते कुछ समय से यह पर्यटन स्थल नाराजगी,असंतोष और शिकायतों के केंद्र में आ गया है, दूर-दराज़ जिलों से सुकून के पल बिताने आने वाले पर्यटक अब खुद को असहज,अपमानित और नियंत्रित महसूस कर रहे हैं,हालात यह हैं कि कई सैलानी यहां से खराब अनुभव लेकर लौट रहे हैं और दोबारा न आने की बात कह रहे हैं, घुनघुट्टा रिसोर्ट आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां प्रशासनिक हस्तक्षेप और पारदर्शी व्यवस्था की सख्त जरूरत है,यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ,तो यह सुंदर स्थल सुकून की पहचान नहीं,बल्कि नाराजगी का प्रतीक बनकर रह जाएगा।

पब्लिक का पैसा, लेकिन पब्लिक के लिए मनाही ?

पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के आरोप बेहद गंभीर हैं रिसोर्ट में घुसने की अनुमति नहीं,घूमने,बैठने,तस्वीर लेने तक पर रोक-टोक,सिर्फ फोटो खिंचवाने भर पर बदतमीजी और अपमानजनक व्यवहार लोग पूछ रहे हैं जब पैसा जनता का है,तो सुविधा जनता को क्यों नहीं?

बदतमीजी का 'अधिकार' किसने दिया ?

सबसे बड़ा सवाल मैनेजर कुशवाहा के व्यवहार को लेकर उठ रहा है, आरोप है कि पर्यटकों से असभ्य भाषा में बात की जाती है,बेवजह रोका जाता है,आदेश ऊपर से है कहकर जिम्मेदारी टाल दी जाती है, यह सवाल अब सार्वजनिक बहस का विषय है किस नियम,किस आदेश और किस अधिकार के तहत कोई मैनेजर जनता से बदतमीजी कर सकता है?

पर्यटन विभाग की भूमिका पर सवाल

पर्यटन विभाग ने मैनेजर को किस उद्देश्य से तैनात किया है? लोगों को सहूलियत देने के लिए? रिसोर्ट को आमजन के लिए सुलभ बनाने के लिए? या फिर नागरिकों को रोकने,अपमानित करने और सार्वजनिक स्थल को निजी जागीर की तरह चलाने के लिए? यदि मैनेजर का व्यवहार सही है,तो विभाग को इसे लिखित नियमावली में सार्वजनिक करना चाहिए, और यदि गलत है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

करोड़ों की संपत्ति कहीं 'निजी रिसोर्ट' तो नहीं बन गई ?

घुनघुट्टा रिसोर्ट को लेकर लोगों में यह धारणा गहराती जा रही है कि यह रिसोर्ट नागरिकों के लिए नहीं,बल्कि कुछ लोगों के निजी नियंत्रण में चला गया है, यह स्थिति न सिर्फ पर्यटन को नुकसान पहुंचा रही है,बल्कि सरकारी छवि और जनविश्वास को भी चोट पहुंचा रही है।

यह सिर्फ रिसोर्ट का मामला नहीं...

यह मुद्दा केवल घुनघुट्टा रिसोर्ट तक सीमित नहीं है,यह सवाल है जनता के अधिकारों का,सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का और सरकारी जवाबदेही का यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए,तो घुनघुट्टा रिसोर्ट सुकून की पहचान नहीं,बल्कि सरकारी उपेक्षा और अफसरशाही की मनमानी का प्रतीक बन जाएगा,अब देखना यह है कि सरकार और पर्यटन विभाग जनता के साथ खड़े होते हैं या एक मैनेजर की मनमानी पर आंख मूंदे रहते हैं।

प्रवेश से ही शुरू हो जाती है परेशानी

पर्यटकों का आरोप है कि रिसोर्ट में प्रवेश प्रक्रिया ही अनावश्यक रूप से कठिन बना दी गई है, कई बार गेट पर ही रोक दिया जाता है,प्रवेश मिलने पर भी कर्मचारियों की कठोर और असहयोगात्मक भाषा का सामना करना पड़ता है, परिसर के भीतर घूमने, बैठने और तस्वीरें लेने तक पर बार-बार टोका जाता है पर्यटकों का कहना है कि वे यहां आराम और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं,न कि किसी अनुशासनात्मक जांच के लिए।

ऊपर बात कर लीजिए...सबसे बड़ी समस्या

शाम 4 बजे या उसके बाद पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए स्थिति और भी खराब बताई जा रही है,कई मामलों में गेट ही नहीं खोला जाता,निवेदन करने पर एक ही जवाब ऊपर बात कर लीजिए पर्यटकों का आरोप है कि फोन पर जिस अधिकारी से बात कराई जाती है,वह अक्सर जिले के बाहर से बात करता है और कठोर शब्दों में मना कर देता है। इससे लोगों में निराशा और आक्रोश और बढ़ जाता है।

नियमों की भरमार, लेकिन नियमावली गायब

एक बड़ा विरोधाभास यह भी सामने आया है कि रिसोर्ट परिसर के अंदर या बाहर किसी प्रकार की लिखित नियमावली प्रदर्शित नहीं है,पर्यटकों को नियमों की पूर्व जानकारी नहीं दी जाती,इसके बावजूद नियमों का हवाला देकर कड़ी रोक-टोक की जाती है,पर्यटकों का कहना है कि प्रबंधन को पहले बुनियादी सुविधाएं सुधारने पर ध्यान देना चाहिए,न कि केवल नियंत्रण और पाबंदियों पर।

सुविधाओं का अभाव,नियंत्रण पर जोर

शिकायतों के अनुसार बैठने,जानकारी देने और मार्गदर्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं,कर्मचारियों का व्यवहार सेवाभाव से दूर नजर आता है,हर छोटी बात पर ऊपर से आदेश का हवाला देकर पर्यटकों को चुप करा दिया जाता है,इससे रिसोर्ट का इको-टूरिज्म का उद्देश्य ही सवालों में आ गया है।

स्थानीय पर्यटन और रोजगार पर असर

घुनघुट्टा रिसोर्ट कोरिया जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय होटल, छोटे दुकानदार, टैक्सी और गाइड, ग्रामीण रोजगार के लिए आय का बड़ा साधन हैं। लगातार बढ़ती नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

सोशल मीडिया पर भी फूटा गुस्सा

बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई पर्यटकों ने रिसोर्ट प्रबंधन के रवैये को लेकर नकारात्मक अनुभव साझा किए हैं, लोगों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो घुनघुट्टा रिसोर्ट की पहचान नकारात्मक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बन जाएगी, जो सोनहत की छवि के लिए घातक होगा।

प्रशासन के सामने अहम सवाल

- क्या पर्यटन स्थल आम नागरिकों के लिए हैं या केवल प्रबंधन की मर्जी पर ?
- बिना लिखित नियमावली के पाबंदियां कितनी जायज हैं ?
- यदि पर्यटक निराश होकर लौटेंगे,तो पर्यटन विकास का लक्ष्य कैसे पूरा होगा ?

सरकार से सीधे सवाल अब सवाल सीधे सरकार और प्रशासन से हैं...

- क्या सार्वजनिक धन से बना रिसोर्ट आम जनता के लिए नहीं है ?
- क्या एक मैनेजर सरकार से ऊपर है ?
- क्या पर्यटन विभाग इस व्यवहार से सहमत है ?
- और सबसे अहम—क्या मैनेजर कुशवाहा पर कार्रवाई होगी या नहीं ?

भाजपा जिलाध्यक्ष का बयान यदि ऐसा हो रहा है तो यह गलत है...

घुनघुट्टा रिसोर्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के कोरिया जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा इस विषय में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह सुविधा क्षेत्र की जनता और पर्यटकों के लिए है, उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिए,मैं इस मामले की जानकारी लेता हूँ और यदि ऐसा हो रहा है, तो यह गलत है,इस बात से सरकार को भी अवगत कराऊँगा,भाजपा जिलाध्यक्ष के इस बयान के बाद अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या पर्यटन विभाग से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाएगी, क्या रिसोर्ट प्रबंधन के व्यवहार की जांच होगी,और क्या जनता व पर्यटकों को वास्तव में उनका अधिकार और सुविधा मिल पाएगी, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह सिर्फ शिकायत का विषय नहीं रहा,बल्कि सरकारी जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है,यदि सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष तक यह मामला पहुँचा है, तो जनता को उम्मीद है कि घुनघुट्टा रिसोर्ट को **निजी नियंत्रण** से निकालकर फिर से सार्वजनिक सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा।

यूथ कांग्रेस का विरोध,आंदोलन की चेतावनी

रिसोर्ट प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साहू ने तीखी नाराजगी जताई है,उन्होंने कहा घुनघुट्टा रिसोर्ट को क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है,न कि पर्यटकों को प्रताड़ित करने के लिए। कांग्रेस नेता अनित दुबे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रिसोर्ट में अघोषित पाबंदियां लगाई जा रही हैं,कर्मचारियों का व्यवहार अभद्र और तानाशाहीपूर्ण है,बाहरी जिलों से आने वाले पर्यटक खराब अनुभव लेकर लौट रहे हैं,जो सोनहत के लिए ठीक नहीं,यूथ कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वे कलेक्टर कोरिया से औपचारिक शिकायत करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर विरोध-आंदोलन भी किया जाएगा।

सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर ईई पीडब्ल्यूडी को दिया गया नोटिस

-संवाददाता-

कोरबा,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व सुगम बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात सुगमता तथा सड़क मरम्मत व सुधार संबंधी विषयों पर गहन समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटनाजन्य स्थानों पर प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए । बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी,वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव,सीईओ जिला पंचायत दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा सभी एसडीएम सहित यातायात,पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई,शिक्षा,वास्थ्य,बाल्को,एसईसीएल एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री दुदावत ने

बैठक में जिले में चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना जन्य क्षेत्रो की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन पर आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अविलंब सुधार कार्य किया जाए। साथ ही सड़कों में आवश्यक स्थानों में मरम्मत कार्य और संकेतकों की व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इन क्षेत्रों पर ब्रेकर्स, स्पष्ट साइनेज, रेडियम पट्टियाँ, तथा पेड़ों और झाड़ियों की छटाई कर दृष्टि बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने निर्देश दिए। राजकीय राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में जुड़ने वाली सड़कों पर ब्रेकर लगाने के लिए कहा। कलेक्टर श्री दुदावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्ल्यूडी व पीएमजीएसवाई विभाग अंतर्गत सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यो के प्रक्रियाधीन टेंडर को जल्द पूरा कराने एवं काम शुरू कराने के निर्देश दिए साथ ही प्रगतिरत निर्माण कार्यो को समय सीमा पर पूर्ण कराने निर्देशित किया। उन्होंने राजमार्गो के तकनीकी खामियों वाले स्थलों पर सुधारात्मक उपाय लागू करने हेतु अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिश जारी करने के दिए निर्देश ।

पाईप लाईन क्षतिग्रस्त को मरम्मत करने के दौरान पानी हुआ मटमैला,जिसे निगम द्वारा सुधारा गया

-संवाददाता-

कोरबा,07 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम कोरबा के वार्ड क्र. 10 भिलाईखुर्द के अंतर्गत आने वाली हाउसिंग बोर्ड कालोनी में आपूर्ति किए गए पानी के मटमैला होने के कारण क्षतिग्रस्त हुई उक्त पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य करना था,पाईप लाईन की मरम्मत के पश्चात अब हाउसिंग बोर्ड कालोनी में शुद्ध व साफ जल की आपूर्ति की जा रही है। कोरबा नगर निगम के कार्यपालन अभियंता जलप्रदाय राकेश मसीह ने बताया कि वार्ड क्र. 10 भिलाईखुर्द अंतर्गत बरबसपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी में जलापूर्ति की जाने वाली पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गई थी,जिसके कारण एक दिन के लिए आकस्मिक रूप से जलापूर्ति बाधित भी हुई थी। निगम द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को मरम्मत करा दिया गया है तथा पाईप लाईन के मरम्मत के कारण स्वभाविक रूप से पानी में मिट्टी घुली,जिसके परिणाम स्वरूप नलों से मटमैला पानी निकला था । उन्होने बताया कि उक्त क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की मरम्मत होने के पश्चात अब नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है।

कार्तिक से नाम जुड़ने पर करीना कुबिलियूट ने तोड़ी चुप्पी:कहा...मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूं,कमेंट सेक्शन ऑफ किया,वेकेशन फोटोज से डेटिंग की अफवाह

कार्तिक आर्यन हाल ही में अपनी गोवा वेकेशन की तस्वीरों से सुर्खियों में आ गए। मंगलवार को कार्तिक ने गोवा से एक तस्वीर शेयर की थी,जिसके ठीक बाद 18 साल की करीना कुबिलियूट की भी ठीक उसी लोकेशन से तस्वीर सामने आई, जहां कार्तिक मौजूद थे। इसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें सुर्खियों में आ गईं। हालांकि चर्चा में आने के बाद करीना ने इस पर रिएक्शन दिया है। करीना ने कार्तिक आर्यन से नाम जुड़ने के बाद अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा था,मैं कार्तिक को नहीं जानती,मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं परिवार के साथ वेकेशन पर हूं। कार्तिक से डेटिंग की खबरों के साथ ही करीना कुबिलियूट के इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में दोनों का नाम जोड़ते हुए कई कमेंट्स किए जाने लगे। ऐसे ही एक कमेंट के जवाब में करीना कुबिलियूट ने लिखा, मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। इसके कुछ देर बाद ही करीना कुबिलियूट ने अपना इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है।

कैसे शुरू हुई डेटिंग की खबरें

मंगलवार को कार्तिक आर्यन ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से गोवा वेकेशन की तस्वीर शेयर की। वो बीच पर लेटे नजर आए। कुछ देर बाद रेडिट में करीना कुबिलियूट की एक तस्वीर वायरल हुई,जिसमें वो ठीक उसी बीच पर, उसी लोकेशन पर थीं, जहां कार्तिक आर्यन थे। रेडिट पर करीना की इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कार्तिक करीना को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। हालांकि दैनिक भास्कर इसकी पुष्टि नहीं करता।

कौन हैं करीना कुबिलियूट?

करीना कुबिलियूट ग्रीस की रहनेवाली हैं, जिनकी उम्र महज 18 साल है। करीना ब्रिटेन में रहकर कार्लिसले कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं, इसके साथ ही वो एक चीयरलीडर भी हैं। शुरुआत में करीना के इंस्टाग्राम पर महज 300 से 400 फॉलोवर्स थे, लेकिन कार्तिक आर्यन से नाम जुड़ने के बाद अब उनके फॉलोवर्स की संख्या 14 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं।

माधुरी दीक्षित भी नहीं बदल पाई इस एक्टर की फूटी किस्मत...विलेन बनकर भी निकला फुस्स

एक एक्टर,जिसे इंडस्ट्री में खूब मौके मिले, फिर भी वो अपनी किस्मत को चमका नहीं पाया। इनका नाम है संजय कपूर। जी हां,अनिल कपूर और बोनी कपूर के भाई। जिन्होंने बतौर लीड हीरो करियर की शुरुआत की,पर विलेन बनकर भी कुछ खास कर नहीं पाएं। बॉलीवुड में कई

सितारों को उभरते तो कईयों को गुम होते हुए देखा गया है। हम उस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं,जिसका कपूर खानदान से नाता है। जिनके दोनों भाई इंडस्ट्री में ऊंचे मुकाम पर हैं। पर वो चाह कर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं पाए। मौके उन्हें खूब मिले,कई बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया,जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है, पर वो भी इस एक्टर को सक्सेस नहीं दिलवा पाई। हम बात कर रहे हैं, संजय कपूर की। संजय कपूर का जन्म 1965 में हुआ था। उनके दो भाई हैं,अनिल कपूर और बोनी कपूर। खानदान में श्रीदेवी,अर्जुन कपूर,सोनम कपूर,जान्हवी कपूर,खुशी कपूर हैं,जो इंडस्ट्री में सक्रिय हैं।

8 की उम्र में ईरान से भागी थी ये हसीना,रिफ्यूजी कैंप में 1 आलू और अंडे के सहारे काटे दिन,तहखाने में रहते थे माता-पिता

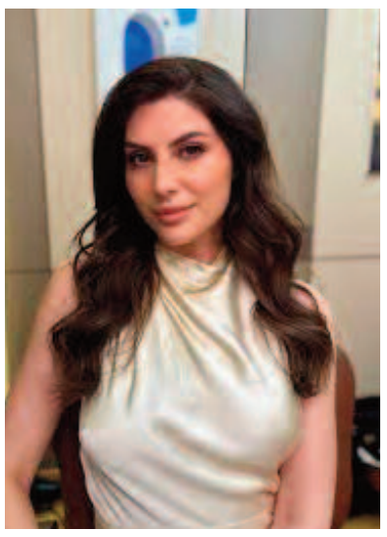

ये बॉलीवुड एक्ट्रेस तब सिर्फ 8 साल की थी, जब ये ईरान छोड़कर भागी थी। इसके बाद इसने रिफ्यूजी कैंप में दिन बिताए,जहां एक अंडा और आलू पर इसे दिन काटना पड़ता था। मुश्किलों में दिन गुजारते हुए इस एक्ट्रेस ने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया।

बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं,जिन्होंने दूसरे देश से आकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। किसी ने मजबूरी तो किसी ने अभिनय की चाह में अपने देश से दूरी बना ली। इनमें से कई कलाकारों को फिल्मी दुनिया में एंट्री से पहले बदहाली के दिन भी देखने पड़े। दर-दर की ठोकरें खाते हुए इन कलाकारों ने अपने लिए फिल्मी दुनिया में जगह बनाई और आज लाखों दिलों पर राज करते हुए लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे,जो 8 साल की उम्र में ईरान से भागी थी और फिर रिफ्यूजी कैंप में कई साल गुजारे। हम बात कर रहे हैं एल्नाज नोरौजी की, जिन्हें एक समय पर एक अंडा और आलू के सहारे अपना पूरा दिन काटना पड़ता था और ये एक अंडा और आलू भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होता था।

ईरान से भागकर पहुंचीं जर्मनी

एल्नाज नोरौजी कई बार अपने संघर्ष भरे दिनों के बारे में बात कर चुकी हैं। एल्नाज तब 8 साल की थीं, जब वह ईरान से भागकर जर्मनी पहुंची थीं। यहां उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में मुश्किल हालातों का सामना किया। एल्नाज को यहां दिन का एक अंडा और आलू मिलता थी, जिसके लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था। फिर एल्नाज ने 14 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया और फिल्मी दुनिया में कदम जमाने की जद्दोजहद में जुट गईं।

पाकिस्तानी फिल्म से शुरू किया करियर

मस्ती 4 और सेक्रेड गेम्स जैसी फिल्म और सीरीज में काम कर चुकीं एल्नाज ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और छोटे-मोटे रोल और डांस नंबर्स में काम किया। एल्नाज ने मस्ती 4, तेहरान जैसी फिल्मों के साथ ही सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज में भी काम किया है।

मुश्किल में गुजरा बचपन

एल्नाज नोरौजी ने हाल ही में साइर ब्रोचा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अपनी निजी जिंदगी पर चर्चा की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने बचपन के संघर्ष का भी खुलासा किया। उन्होंने इस बातचीत में कहा-बहुत से लोगों को लगता है कि मैं एक रिच परिवार से हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक अमीर परिवार से नहीं हूं। हम ईरान के बहुत छोटे से घर में रहते थे, मुझे तेहरान बहुत पसंद था। लेकिन,जब हम तेहरान से भागकर जर्मनी के एक छोटे से शहर में पहुंचे,तब फर्क समझ आया। पहले तो हम एक रिफ्यूजी कैम्प में रहे। हम बिना किसी पेपरवर्क के जर्मनी पहुंचे थे और वहां सबकुछ अलग था

छोटे कमरे में किया गुजारा

इसी बातचीत में एल्नाज ने कहा...सोचिए आप मुंबई जैसे शहर में पले-बढ़े हों और अचानक ऐसे शहर में पहुंच जाएं,जहां सब कुछ 6 बजे तक बंद हो जाता हो। मैं अपने मां-पापा के साथ एक बहुत छोटे से कमरे में रहती थी। वहां अलग-अलग परिवारों के लिए अलग-अलग कमरे होते थे,लेकिन बाथरूम सिर्फ एक ही था और एक ही रसोईघर। इस कमरे में तीन बिस्तर थे। खाने के लिए रोज लाइन में खड़े होना पड़ता था,जहां एक अंडा और आलू मिलता था। यही रिफ्यूजी लाइफ है। आज भी मुझे बिना मसाले के आलू और अंडे खाना पसंद है। मुझे इससे अपना बचपन याद आता है।

एल्नाज को आती हैं 7 भाषाएं

एल्नाज आगे कहती हैं- जर्मनी पहुंचकर काम करने के लिए जर्मनी भाषा आना जरूरी था। हमें जर्मनी नहीं आती थी। मैंने अपनी मां के साथ जर्मनी सीखी और पढ़ाई जारी रखी। फिर वहीं मैंने देवनागरी और उर्दू सीखी। मैं अब सात भाषाएं बोल सकती हूं। मैं जब पैदा हुई थी, मेरे माता-पिता तहखाने में रहते थे। हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। हम उन कुछ लोगों में से थे,जो जल्दी ही कैंप से निकल गए। लेकिन, यहां से निकलने के लिए आपको महत्वाकांक्षी होना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष के बाद जीवन आरामदायक लग सकता है। आपको किसी चीज के लिए पैसे नहीं देना पड़ता।

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का वो पक्का दोस्त,अपनी ही एक्स वाइफ के प्यार में हुआ क्लीन बोल्ड,8 साल बाद लिया था तलाक

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के पक्के दोस्त गुलशन देवैया अपनी एक्स वाइफ को डेट कर रहे हैं। शादी के 8 बाद उन्होंने तलाक लिया था। कांतारा,कमांडो और हेट स्टोरी जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से तारीफें बटोरने वाले एक्टर गुलशन देवैया इन दिनों फिर से प्यार में हैं। साल 2012 में गुलशन ने शादी की थी और 2020 में तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के कुछ ही समय बाद फिर से गुलशन को प्यार हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि उन्हें प्यार अपनी ही एक्स वाइफ से हुआ है और तलाक के बाद फिर से डेट कर रहे हैं। हाल ही में गुलशन ने इसका खुलासा किया है। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के पक्के दोस्त गुलशन ने ही दोनों के रिश्ते के खुलासा किया था। अब गुलशन ने हाल ही में बताया कि वे अपनी एक्स वाइफ को डेट कर रहे हैं। आइये जानते हैं कौन हैं गुलशन की एक्स वाइफ जिनकी ग्रीक ब्यूटी पर गुलशन फिर से क्लीन बोल्ड हो गए हैं।

8 साल चली थी पहली शादी

गुलशन देवैया ने अनुराग कश्यप की 2010 में आई फिल्म दैड गर्ल इन येलो बूट से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद गुलशन को काफी पहचान मिली और बॉलीवुड में करियर चल निकला। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्रीस की रहने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस किल्होरी तेजीआप्ता से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और प्यार हो गया। साल 2012 में गुलशन और किल्होरी ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों काफी खुश थे और करियर में खूब तरक्की करते रहे। हालांकि दोनों की ये लवस्टोरी महज 8 साल तक ही चल पाई और साल 2020 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। 8 साल बाद गलुशन और किल्होरी ने तलाक ले लिया।

कौन हैं गुलशन की पत्नी और ग्रीक ब्यूटी?

ग्रीस की रहने वाली किल्होरी तेजीआप्ता एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड में काम करती हैं। किल्होरी ने बॉलीवुड की कुछ वेबसीरीज में भी काम किया है। मेड इन हैवेन 2, बार्ड ऑफ ब्लड जैसी कहानियों में किल्होरी ने दमदार किरदार निभाए हैं। इसके साथ ही किल्होरी ने फिल्मों में भी काम किया है और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म दिल धड़कने दो में भी काम किया है।

तलाक के बाद फिर से कर रहे डेट

गुलशन और किल्होरी ने शादी के 8 साल बाद तलाक लिया था और एक बार फिर से प्यार में पड़ गए हैं। बीते 2 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब गुलशन और किल्होरी फिर से शादी कर सकते हैं। गुलशन ने बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है और बताया है कि अब मैं फिर से अपनी एक्स वाइफ को डेट कर रहा हूं।

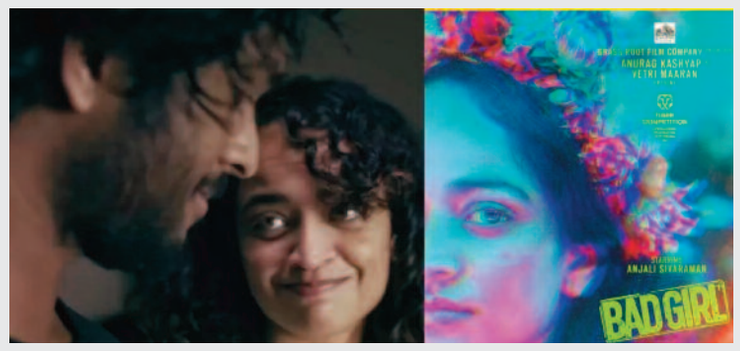

लड़कों की गर्दन पर पसीने की बूंदें देख उत्तेजित हो जाती थी हीरोइन,कहानी ऐसी कि ठनक गया था लोगों का माथा

फिल्मों में हीरोइन की परंपरागत इमेज काफी आदर्श किस्म की कहानी। हीरोइन के किरदारों में फैमिनाइन जेंडर का अफेक्शन, प्यार और कोमलता तो लोगों ने पर्दे पर लंबे समय से देखी है। लेकिन बीते साल 2025 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसकी हीरोइन के खूब चर्चे हुए। इतना ही नहीं ये हीरोइन लड़कों की गर्दन पर पसीने की बूंदें देख उत्तेजित हो जाया करती है। साथ ही अपने सेक्सुअल फैंटेसीज को दबाने की वजाय उसे जीना चुनती है। लेकिन इस फिल्म की कहानी को देख लोगों का माथा ठनक गया था और खूब विरोध हुआ था। विरोध के बाद भी इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होने के बाद लोगों ने खूब प्यार दिया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म बैड गर्ल की।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी राम्या नाम की लड़की की है जिसका किरदार अंजलि शिवारमन ने निभाया है। राम्या एक तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई है और उसकी मां एक शिक्षक है। इस तरह के आदर्श परिवार में राम्या पर भी उसी तरह से रहने और एक परंपरागत लड़की होने का दवाब है। लेकिन राम्या स्कूल के दिनों से ही अपनी सैक्सुअल फैंटेसीज को चेज करने का चुनाव करती है। स्कूल में क्लास के दिनों में लड़कों की गर्दन पर पसीने की बूंदें देख राम्या उत्तेजित हो जाती है। इतना ही नहीं हमेशा वाइल्ड फैंटेसी जीने का सपना देखती है। फिल्म की कहानी का उद्देश्य हीरोइन्स की परंपरागत इमेज को तोड़ना है। जिसमें ये बताया जाता है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह अपनी फैंटेसी को दबाने की जगह उसे जीने की इच्छा रखती हैं।

विरोध की आंधी झेलती रही थी फिल्म

फिल्म बैड गर्ल को डायरेक्टर वर्षा भरथ ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने खुद ही इसकी कहानी भी लिखी है। फिल्म में हीरोइन एक ब्राह्मण तमिल परिवार से आती है और इसकी कहानी के एडल्ट नेचर को देखते हुए लोगों का माथा ठनक गया था।

खेल समाचार

निखत,पवन और सुमित क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निकहत ज़रीन,वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फ़ाइनल 2025 के गोल्ड मेडलिस्ट पवन बर्तवाल और सुमित ने अपने-अपने विरोधियों पर दबदबा बनाया,जबकि ज़्यादातर दूसरे टॉप खिलाड़ियों ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी,ग्रेटर नोएडा में बुधवार को एलीट पुरुष और महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आसान जीत के साथ अपने-अपने वेट कैटेगरी के क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई। यह पहली बार है कि पुरुष और महिला नेशनल चैंपियनशिप एक ही जगह पर एक साथ हो रही हैं और देश भर से 600 बॉक्सर पुरुष और महिलाओं के लिए 10-10 वेट कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं की 48-51केजी कैटेगरी में,तेलंगाना की बॉक्सर के दबदबे के कारण रेफरी ने निकहत और लद्दाख की कुलसूमा बानो के बीच मुकाबला पहले राउंड में ही रोक दिया,जबकि पवन (पुरुष 50-55) ने ललित को और सुमित (पुरुष 70-75केजी) ने मध्य प्रदेश के कपिल को हराया, दोनों मुकाबले तीसरे राउंड में रोके गए। इससे पहले, वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी (महिला 45-48केजी) ने झारखंड की अन्नू पर 5:0 से आसान जीत के साथ अपना मार्च जारी रखा। पुरुषों की 50-55केजी कैटेगरी में, जादुमणि सिंह ने उत्तर प्रदेश के मनीष राठौर को 5:0 से आसानी से हराया, जबकि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अमित पंघाल ने चंडीगढ़ के कृष पाल को 4:1 से हराया। मंगलवार को,वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट पूजा रानी और इंडिया इंटरनेशनल जादुमणि सिंह ने आसान जीत दर्ज की, जबकि टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और अनुभवी खिलाड़ी अमित पंघाल को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हरियाणा की पूजा (75-80केजी) ने चंडीगढ़ की अंजू को 5-0 से हराकर अपनी क्लास साबित की,जबकि जादुमणि (50-55केजी) तमिलनाडु के आर पार्थिबन पर इतने हावी थे कि रेफरी ने मुकाबला दूसरे राउंड में ही रोक दिया। हालांकि,दो अन्य स्थापित सितारों के लिए यह आसान नहीं था। स्वीटी ने असम की लवलीना को कड़ी टक्कर दी,जिसके बाद अनुभवी खिलाड़ी ने 3-2 के स्प्लिट फैसले से जीत हासिल की।

भारत -19 ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से हराया

वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी बनाई,आरोन जॉर्ज का भी शतक

नई दिल्ली,07 जनवरी 2026। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे अंडर-19 वनडे में 63 बॉल पर शतक लगाया। उनकी इस पारी के सहारे भारत ने 233 रन की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में कप्तानी भी की।14 साल के वैभव ने 74 बॉल पर 127 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 10 छक्के और 9 चौके लगाए। वैभव ने आरोन जॉर्ज के साथ 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। आरोन जॉर्ज ने 118 रन की पारी खेली। बेनोनी के विलोमूर पार्क स्टेडियम में भारत ने 50 ओवर में 7

विकेट पर 393 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 35 ओवर में 160 रन पर ऑलआउट हो गई। किशन सिंह ने 3 विकेट झटके। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे।

सूर्यवंशी अब विराट से महज 5 रन पीछे

वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की सूची में विराट कोहली से महज 5 रन पीछे हैं। वे 18 मैचों में 973 रन बना चुके हैं। जबकि कोहली ने 28 मैचों में 46.57 के एवरेज से 978 रन बनाए हैं। अब तक वैभव का एवरेज (54.05) विराट से अच्छा है।इस सूची में सबसे ज्यादा विजय जोल ने बनाए हैं। विजय के नाम 36 मैचों में 1404 रन हैं। यशस्वी जायसवाल (1386 रन) दूसरे और तन्मय श्रीवास्तव (1316 रन) तीसरे नंबर पर हैं। उन्मुक्त चंद, सरफराज खान और शुभमन गिल भी इस लिस्ट में वैभव से ऊपर हैं।

भारतीय टीम में 2 बदलाव

भारतीय टीम ने इस मैच में अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। इस मैच में दीपेश देवेंद्रन और खिलन पटेल को आराम दिया गया है। उनकी जगह उद्धव मोहन और हेनिल पटेल की प्लेइंग 11 में जगह मिली है।

दूसरे वनडे में 19 बॉल पर फिफ्टी लगाई थी

इससे पहले वैभव ने सोमवार को साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम के खिलाफ 19 बॉल पर फिफ्टी बनाई थी। उन्होंने 24 बॉल में 68 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और एक चौका भी जमाया था। इस तरह उन्होंने 68 में से 64 रन बाउंड्री से बनाए थे।

भारत सीरीज में 2-0 से आगे

भारत तीन मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। टीम ने पहला मैच 25 रन और दूसरा मैच 8 विकेट से जीता था।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत:- आरोन जॉर्ज,वैभव सूर्यवंशी (कप्तान),वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया,आरएस अंबरीश,कनिष्क चौहान,मोहम्मद एनान,खिलान पटेल,उधव मोहन, हेनिल पटेल।

साउथ अफ्रीका:-: जोरिच वान शल्कविक,अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन राउल्स,डेनियल बोसमैन, पॉल जेम्स,लेथाबो फाह्लामोहलाका (विकेटकीपर), कॉर्न बोथा,माइकल क्रुइस्कैम्प, जे जे बैसन,एनटांडो सोनी।

सार्थक-हार्डी ने डब्ल्यूटीटी फीडर 2026 में तीसरी वरीयता को हराया

वडोदरा,07 जनवरी 2026। सार्थक आर्य और हार्डी पटेल ने तीसरे सीड स्नेहित सुरावज्जुल और सायली वानी को 5-11, 11-9, 11-9, 9-11, 12-10 के स्कोर से हराकर मिक्स्ड डबल्स क्वालिफाइंग के दूसरे राउंड में जगह बनाई। इस बीच, टॉप सिंगल्स खिलाड़ियों ने बुधवार को सामा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ गुजरात द्वारा स्पॉन्सर डब्ल्यूटीटी फीडर सीरीज़ 2026 में अपने शुरुआती ग्रुप मैच आसानी से जीत लिए। वडोदरा में डब्ल्यूटीटी फीडर सीरीज़ का पहला एडिशन, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ गुजरात ने होस्ट किया है, टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ़ बड़ौदा द्वारा आयोजित किया गया है और यूटीटी द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। सिंगल्स ग्रुप स्टेज में, पुरुषों में यशांश मलिक, संयोग कपाली और जश मोदी, साथ ही महिलाओं की कैटेगरी में सेलेना सेल्वकुमार, नित्या मणि और संपदा भिवंडीकर ने अपने शुरुआती मैच जीते।

सूरमा हॉकी क्लब ने महिला हॉकी इंडिया लीग में फाइनल जीत के साथ धमाका किया

रांची,07 जनवरी 2026। एक रिलीज़ के अनुसार,जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने मंगलवार को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में फाइनलिस्ट श्राची बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 3-2 की शानदार जीत के साथ अपने महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 अभियान का समापन किया। हालांकि यह मैच सिर्फ औपचारिकता थी, क्योंकि सूरमा पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुकी थी और टाइगर्स का फाइनल में पहुंचना तय था, फिर भी दोनों टीमों ने पूरी शिद्दत

से खेला और दर्शकों का मनोरंजन किया। यह एक करीबी मुकाबला था जो आखिरी पलों तक चला। सूरमा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया, शुरुआती सीटी बजते ही आक्रामक तरीके से दबाव बनाया और टाइगर्स को जल्द ही बैकफुट पर धकेल दिया। ओलिविया शैनन सूरमा के आक्रामक खेल के केंद्र में थीं और चौथे मिनट में उन्होंने लगभग एक मौका बना ही लिया था, हालांकि स्कोरलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद कप्तान सलीमा टेटे ने गोल के करीब से एक शॉट लगाया जो गोलकीपर के ऊपर से निकल गया, फिर आठवें मिनट में शैनन ने टाइगर्स की कप्तान जेनिफर रिज़ो को एक शॉट से टेस्ट किया, जिसे उन्होंने आसानी से बचा लिया।

सुकमा में 26 नक्सलियों का बड़ा आत्मसमर्पण

65 लाख के इनामी माओवादियों ने छोड़ी हिंसा

सुकमा,07 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। मंगलवार को नक्सलवाद का दामन छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लेते हुए 26 माओवादियों ने पुलिस और सुरक्षाबलों के आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 13 बेहद खूंखार थे, जिन पर कुल मिलाकर 65 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

'पूना मार्गेम' अभियान और पुनर्वास नीति का दिख रहा व्यापक असर

सुकमा पुलिस के अधिकारियों ने इस बड़ी कामयाबी का श्रेय छत्तीसगढ़ शासन की नई 'नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025' को दिया है। इसके साथ ही सुकमा पुलिस द्वारा संचालित 'पूना मार्गेम' (नई सुबह) अभियान ने भी नक्सलियों के मन को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस शिविरों की लगातार स्थापना और विकास कार्यों की पहुँच से नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव और पुनर्वास नीति के फायदों से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के सामने अपने हथियार डाले।

10 लाख का इनामी डिप्टी कमांडर लाली भी हुआ मुख्यधारा में शामिल

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मुचाकी आयते उर्फ लाली (35 वर्ष) का है। लाली,नक्सलियों की सीआरसी कंपनी नंबर 1 के प्लाटून नंबर दो का डिप्टी कमांडर था, जिस पर शासन ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा था। लाली का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद हिंसक रहा है,उस पर 2017 में सोनाबेड़ा-कोरापुट मार्ग पर सुरक्षाबलों के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाने का आरोप है। इस दर्दनाक हमले में 14 बहादुर जवान शहीद हुए थे। लाली के आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।

इनामी नक्सलियों की लंबी फेहरिस्त महिला कैडरों ने भी छोड़ा साथ

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजनल कमेटी सदस्य हेमला लखमा (41), कंपनी नंबर सात की सदस्य आसमिता उर्फ कमलू सन्नी (20), रामबत्ती उर्फ संध्या (21) और बटालियन नंबर एक का सदस्य सुंडाम पाले (20) प्रमुख हैं। इन चारों खूंखार नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके अलावा, तीन नक्सली ऐसे हैं जिन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम है, जबकि अन्य पर 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के इनाम घोषित थे। इन सात महिला नक्सलियों के सरेंडर से स्पष्ट है कि अब संगठन के भीतर महिलाओं का भी मोहभंग हो रहा है।

नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ते कदमः पुलिस अधीक्षक का बयान

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने इस मौके पर अन्य सक्रिय नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों में लगातार खुल रहे सुरक्षा कैंपों ने नक्सलियों की सप्लाई लाइन और संचार को ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीण अब विकास के साथ जुड़ रहे हैं और नक्सलियों को अब स्थानीय समर्थन मिलना बंद हो गया है।

पुनर्वास नीति के तहत मिलेगी वित्तीय सहायता और सुरक्षा

राज्य सरकार की 'छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025' के तहत इन सभी पूर्व माओवादियों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि सभी 26 सदस्यों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और पुनर्वास योजना के अन्य लाभ जैसे घर,शिक्षा और स्वरोजगार की सुविधा भी नियमनुसार दी जाएगी। शासन का लक्ष्य है कि ये लोग समाज का हिस्सा बनकर सम्मानजनक जीवन जी सकें।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज

डिजिटल गणना करेगी सरकार,केंद्र सरकार ने गृह विभाग को बनाया नोडल

रायपुर,07 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह गणना डिजिटल पैटर्न पर होगी। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए गृह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और भारत सरकार,जनगणना निदेशालय तथा राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा। निदेशक जनगणना कार्तिकेय गोयल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा,डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत जानकारी दी।

मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह : निदेशक ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा,जबकि निगरानी और प्रबंधन वेब पोर्टल से होगा। इस बार नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी मिलेगी,जिससे वे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।

63 हजार कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी : बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जनगणना जैसे बड़े काम के लिए राज्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों और पर्यवेक्षकों सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक कार्मिकों की आवश्यकता होगी। जनगणना के पहले चरण से पहले पूर्व-परीक्षण का कार्य नवंबर 2025 में कबीरधाम जिले के कुकदूर, महासमुंद जिले की महासमुंद तहसील के चयनित ग्रामों और रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन अनुभवों को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।

1 अप्रैल से होगी गणना : मुख्य सचिव ने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। मानसून और स्कूल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अवधि तय करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में देशभर में एक साथ जनसंख्या गणना होगी, जिसके मद्देनज़र स्कूल शिक्षा विभाग को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

महासमुंद में एम्बुलेंस से 2.60 करोड़ का गांजा जब्त

दवाइयों के कार्टून और सीट के नीचे छिपाया,ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे,3 तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद,07 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 2.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गांजे को तस्कर ओडिशा के भवानीपटना जिले से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने महासमुंद में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस के मुताबिक तस्करों ने एम्बुलेंस में सीट के नीचे चैंबर बनाकर गांजा छिपाया था। इसके अलावा दवाइयों के कार्टून में भी गांजा रखा था। गांजा तस्करी के लिए आरोपियों ने महाराष्ट्र पासिंग एम्बुलेंस पर ओडिशा की फर्जी नंबर प्लेट (OD 02 AX 5501) का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह मामला कोमाखान थाना के टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट का है।

ओडिशा से महाराष्ट्र जा रही थी गांजा की खेप

दरअसल, कोमाथाना पुलिस को मंगलवार को सोर्स से जानकारी मिली थी कि एक एम्बुलेंस में बड़ी मात्रा में गांजा लोड है,जो ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर जा रही है। एम्बुलेंस में 3 लोग सवार हैं। सूचना मिलते ही कोमाखान थाना की पुलिस एक्टिव हो गई। कोमाखान थाने की पुलिस ने ओडिशा-छत्तीसगढ़ बार्डर के टेमरीनाका पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू की।

दवाइयों के कार्टून के नीचे मिला गांजा

एम्बुलेंस की तलाशी लेने पर उसमें दवा के 16 कार्टून मिले। पुलिस ने कार्टून को खुलवाकर देखा तो उसके दवाइयों के नीचे गांजा रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस की सीट के नीचे तलाशी ली तो उसमें चैंबर मिला,जिसमें 14 प्लास्टिक बोरियां बरामद हुई। प्लास्टिक की बोरियों में गांजा छिपाकर रखे गए थे। बोरियों से कुल 5 क्विंटल 20 किलो गांजा भरा मिला। पुलिस ने गांजे के साथ-साथ 4 मोबाइल फोन और एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया। जब्त किए गए कुल सामान की कीमत 2,65,10,500 रुपये आंकी गई है। आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

महासमुंद में एंबुलेंस से 5 क्विंटल गांजा जब्त : महासमुंद की एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि 6 जनवरी को टेमरीनाका चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस की निगरानी थी। इसी दौरान महाराष्ट्र की तरफ से जाने वाली एक एम्बुलेंस पर शक हुआ। एम्बुलेंस पर ओडिशा का नंबर प्लेट था और यह टूटी-फूटी हालत में थी। पुलिस ने एम्बुलेंस की तलाशी ली। तलाशी में पता चला कि दवाइयों के पैकेट, सीट के नीचे चैंबर बनाकर गांजा छिपाकर रखा गया था। कुल गांजे की मात्रा 5 क्विंटल 20 किलो थी और इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्राथमिक स्कूल में मचा हड़कंप...एक के बाद 19 बच्चे हुए बेहोश,रतनजोत का फल खाने के चलते हुई थी ऐसी हालत

खैरागढ़, 07 जनवरी 2026। छुईखदान-गंडई जिले के करमतरा स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में सुबह के वक्त स्कूल लगते ही प्रार्थना के दौरान अचानक हड़कंप मच गया,जब बच्चे एक-एक कर चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे। इस दौरान पता चला कि स्कूल खुलने से पहले पहुंचे बच्चों ने स्कूल परिसर के आसपास लगे रतनजोत के पौधे का फल खा लिया था। इसके बाद कई बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालबांधा लाया गया,जहां इनका उपचार किया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ बच्चों पर असर ज्यादा होने के कारण सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ लाया गया,जबकि बाकी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस दौरान तीन बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें खैरागढ़ रेफर किया गया है। घटना की खबर फैलते ही करमतरा गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में पालक और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल परिसर में दहशत और चिंता का माहौल है।

कलेक्ट्रेट में ठेकेदार ने की खुदकुशी करने की कोशिश

बेमेतरा,07 जनवरी 2026। कलेक्टोरेट में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया,जब एक युवक ने खुद की जान लेने की कोशिश की. युवक अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंचा था। उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लिया था, हालांकि समय रहते सुरक्षा में तैनात जवानों ने युवक के पास से माचिस छीन लिया। इससे बड़ी घटना होने से टल गई। जानकारी के मुताबिक,युवक आरिफ बाठिया ने कृषि विभाग के कार्यालय का भवन निर्माण का काम किया था। जिसका पैसा 1 साल बाद भी नहीं मिल पाने की वजह से वह परेशान था। युवक ने अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इसके बाद युवक ने कलेक्टोरेट के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। वह माचिस जलाता, इससे पहले ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया।

नगरीय प्रशासन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध,दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश

रायपुर,07 जनवरी 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। सुडा ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सभी निकायों को इस संबंध में की गई कार्यवाहियों की जानकारी हर महीने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मिशन संचालक को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सुडा ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे परिपत्र में स्वच्छता दीदियों के द्वारा डोर-टू-डोर सिंगल यूज प्लास्टिक के

वैकल्पिक उपायों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उपयोग करने पर लगेगा आर्थिक दंड : सुडा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों, साप्ताहिक बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों,रहवासी कल्याण संघों एवं स्वसहायता समूहों की सहभागिता से घर-घर जागरूकता अभियान संचालित करने के लिए भी सभी निकायों को निर्देशित किया गया है।

विशेष अभियान चलाने के निर्देश

सुडा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों,शैक्षणिक संस्थानों,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों व विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता अभियान के साथ ही शहर के तीर्थ स्थलों,पर्यटन स्थलों,मुख्य चौक-चौराहों, बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन,निस्तारी एवं गैर-निस्तारी तालाबों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सहभागिता से जन-प्रतिनिधियों,धार्मिक गुरूओं, गणमान्य नागरिकों,स्वच्छताग्राहियों,ब्रांड अम्बैसडर्स,एन.जी.ओ. एवं स्वसहायता समूहों को शामिल कर विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

कराए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम

परिपत्र के माध्यम से नगरीय निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए आयोजित सभी कार्यक्रमों को लोकल/क्षेत्रीय मीडिया/नगरीय निकाय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रसारित व पोस्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने निकायों को चित्रकला प्रतियोगिता,नुक्कड़ नाटक एवं वेस्ट-टू-आर्ट प्रतियोगिताओं का भी आयोजन विद्यालय स्तर पर करने को कहा गया है।

सीबीआई ने रिश्वत लेते ब्रांच मैनेजर को किया गिरफ्तार,ऐसे जाल बिछाया

बस्ती,07 जनवरी 2026। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यूपी ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की बेरता ब्रांच (मखौड़ा धाम) के ब्रांच मैनेजर और एक निजी व्यक्ति को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। यह निजी व्यक्ति बैंक में चपरासी के रूप में काम करता था। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। यह मामला

5 जनवरी को दर्ज किया गया, जब एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था।

सौम्या चौरसिया को ईडी के बाद ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर

हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका,शासन ने जवाब पेश करने मांगा समय

बिलासपुर,07 जनवरी 2026। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। लिहाजा,अब गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल,शराब घोटाले के केस में ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए ईडी की स्पेशल बेंच में आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके चलते अब सौम्या चौरसिया को इस केस में ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। यही वजह

है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है।

कहा- झूठे केस में फंसा रही है सरकार : सौम्या के वकील ने हर्षवर्धन पगनिहा ने कहा कि, ईडी की टीम ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत इस केस की जांच की है। जिसके बाद सुनियोजित साजिश के तहत फंसाने के लिए मामले को ईओडब्ल्यू को सौंपा है। ढाई साल पुराने इस केस में सौम्या चौरसिया का कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर परेशान करना चाहती है। बता दें कि शराब घोटाले से संबंधित मामलों की 13 जनवरी से ट्रायल भी शुरू होना है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी दर्ज कराई है। जिसमें 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा,आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)